

S. S. Hussain I.A.S. (Ex)

Chief Executive Officer

Ref. No. MCHI/CEO/17-18/145

February 16, 2018

Sub: Clarification regarding appraisal of cases for grant of Environmental Clearance for Construction projects above 3,00,000 sq. mtrs. BUA under provisions of the EIA Notification dated 14.09.2006 in light of the order passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 08.12.2017

- Ref:**
1. Environmental Impact Assessment notification issued by Ministry of Environment & Forest u/no S.O. 1533 dated 14th September 2006.
 2. Amendment in Environmental Impact Assessment notification issued by Ministry of Environment & Forest & Climate Change u/no S.O. 3999 (E) dated 9th December 2016.
 3. National Green Tribunal Orders dated 8th December 2017 in Application No 677 of 2016 (M.A No 148/2017).
 4. Circular issued by Environment Department, Government of Maharashtra bearing reference no. NGT-2017/CR-45/SEIAA dated 29th January 2018.

Dear *Shri Bharti ji*

This has a reference to the above mentioned Environmental Impact Assessment Notifications issued by the Ministry of Environment Forest and Climate Change and its subsequent amendment issued u/no S.O. 3999 (E) dated 9th December 2016. Copy of the said Notification, is attached herewith for easy reference.

The said Notification dated 9th December 2016 was challenged before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi by filing Original Application Nos. 677 of 2016, 01 of 2017, 07 of 2017 and 55 of 2017, which has been decided by the Hon'ble Tribunal by passing an order dated 8th December 2017. Copy of the said Judgement is attached herewith for easy reference.

Thereafter, the Environment department of Government of Maharashtra, relying upon opinion from the Law & Judiciary department, Government of Maharashtra, issued circular bearing reference no. NGT-2017/CR-45/SEIAA dated 29th January 2018. The Law & Judiciary Department has opined that "the un-amended provisions of the EIA Notification, 2006 are in force and can be implemented by SEACs and SEIAA." Relying on this opinion, the concerned SEACs/SEIAAs, were directed to implement the provisions the EIA Notification, 2006 until further orders from your Ministry. Copy of the said Circular is attached herewith for easy reference.

In compliance to the aforesaid circular, the SEACs and SEIAA have started appraisal of applications for grant of prior Environment Clearance received from the project

proponents for building and construction projects $\geq 20,000$ sq.mtrs and $\leq 1,50,000$ sq.mtrs in addition to the building and construction projects $\geq 1,50,000$ sq.mtrs and $\leq 3,00,000$ sq.mtrs. The circular also states that the powers originally vested with the SEACs/SEIAA under provisions of the EIA Notification dated 14th September 2006 are in force in light of the aforesaid Judgement.

In light of the above, we request for immediate issuance of necessary directions/clarifications, in regards to the applicability and implementations of the EIA Notification, 2006 as amended u/no S.O. 3999 (E) dated 9th December 2016, to building and construction projects $\geq 3,00,000$ sq.mtrs, so it becomes clear to project proponents / stakeholders regarding the next steps to be taken in this regard.

In addition, we request your kind office to issue the environmental clearances for the proposals that were appraised before the Hon'ble NGT order.

To re-iterate, the issuance of directions/clarifications is required on immediate basis in order to fulfil the objective of 'Housing for All by 2022' which is in conformity with the constitutional mandate and also acknowledged as social cause by the NGT in its order dated 8th December 2017.

In view of the above facts, kindly consider our above prayers and do the needful please.

Kindly acknowledge and oblige.

Best regards

Yours *Sincerely*



(S. S. Hussain)

To,
Shri Gyanesh Bharti (I.A.S.)
Joint Secretary
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India
New Delhi - 110 003

Enclosures: As above



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2910]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938

No. 2910]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3999(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा यह निदेश दिया था कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नवीन परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तारण या आधुनिकीकरण के कार्य को, जिसमें प्रक्रिया या तकनीक और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता में वृद्धि किया जाना सम्मिलित है, भारत के किसी भाग में केवल, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेने के पश्चात् ही आरंभ किया जाएगा ;

केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी कारबार करने की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है और भवन तथा संनिर्माण सेक्टर, जो आवास की व्यवस्था करने के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए अनुज्ञाओं को सरल बना रही है तथा इस प्रयोजन के लिए शहरी क्षेत्र में कमजोर वर्ग सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की स्कीम में महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में यह उपबंधित है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी उद्योग पर प्रतिषेध या निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने चाहिए, तो वह अपने ऐसा करने के आशय की सूचना देगी ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना का.आ.1595(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना पर आक्षेप और सुझाव ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से उक्त अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन में आमंत्रित किए जाते हैं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--(I) उक्त अधिसूचना में,--

(1) पैरा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“14. निर्माण उप नियमों में पर्यावरणीय शर्तों का समाकलन :-

- (1) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्माण अनुमति सहित समाकलित पर्यावरणीय दशा प्रदान की जाएगी और आकार के अनुसार इमारतों का निर्माण परिशिष्ट XIV में दिए गए लक्ष्य और निगरानी योग्य पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार किया जाएगा ।
- (2) राज्य जो अपनी भवन उपविधियों तथा सुसंगत राज्य विधियों में उप पैरा (1) में निर्दिष्ट इन लक्ष्यों तथा निगरानी योग्य पर्यावरणीय शर्तों को अपना रहे हैं और भवन संनिर्माण के लिए दिए गए अनुमोदनों से उन शर्तों को समाविष्ट कर रहे हैं जिससे इसे विधिक रूप से प्रवर्तनीय बनाया जा सके, व्यष्टिक इमारतों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी ।
- (3) राज्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी उपविधियों और नियमों में ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन भेजेंगे जो प्रारूप की समीक्षा करेगा और सहमति देगा ।
- (4) जब राज्य सरकारों, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सहमति दिए गए उपविधियों और नियमों को अधिसूचित कर देती हैं तो केन्द्रीय सरकार यह आदेश जारी करेगी कि उन राज्य या स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्रों में कोई पृथक् पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है ।
- (5) स्थानीय प्राधिकारियों जैसे विकास प्राधिकरण, नगरपालिकाएं स्थानीय निकायों में गठित पर्यावरण प्रकोष्ठ की सिफारिशों पर किन्हीं भवनों के लिए नियत अपेक्षाओं के अनुसार यथा लागू किए गए समापन प्रमाणपत्र के जारी किए जाने से पूर्व इन पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन प्रमाणित करेंगे ।
- (6) राज्य सरकारें जहां उपविधि या नियम विरचित नहीं है, इस अधिसूचना में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, व्यष्टिक परियोजनाओं के मूल्यांकन की विद्यमान प्रक्रिया तथा इमारतों और संनिर्माणों के लिए पर्यावरण अनापत्ति की मंजूरी का पालन करते रहेंगे ।”
- (7) भवनों में पर्यावरण के समावेशन के संबंध में प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सक्षम अभिकरण के माध्यम से अर्हित निर्माण पर्यावरणीय संपरीक्षक से इस अधिसूचना की अपेक्षाओं के माध्यम से निर्माण परियोजना का मूल्यांकन और प्रमाणित करेगी तथा अर्हित निर्माण पर्यावरणीय संपरीक्षक का प्रत्यानन के लिए प्रक्रिया और उनकी भूमिका परिशिष्ट XV पर दी गई है ।
- (8) निर्माण उपविधि में पर्यावरण शर्तों के समामेलन के अनुपालन में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी पर्यावरण प्रकोष्ठ (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रकोष्ठ कहा गया है), गठन करेगी तथा अपने क्षेत्राधिकार में पर्यावरण योजना को सुनिश्चित करेगा ।
- (9) प्रकोष्ठ इमारतों के निर्माण के लिए पर्यावरण शर्तों के समाकलित करने के लिए बनाए गई उपविधि और नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगा और प्रकोष्ठ किसी असावधानी, यदि कोई है, के लिए तृतीय पक्षकार संपरीक्षा प्रक्रिया की भी अनुमति देगा ।
- (10) प्रकोष्ठ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।
- (11) प्रकोष्ठ का गठन और कृत्य परिशिष्ट xvi में दिया हुआ है ।
- (12) स्थानीय प्राधिकारी निर्माण उपविधि में पर्यावरण के संबंध में समाकलन करते समय परियोजना में उनकी सरकार के अनुसार नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी :-

भवन प्रवर्ग ‘I’ (5000 से < 20,000 वर्ग मीटर)

पर्यावरणीय शर्तों (परिशिष्ट xiv) के अनुपालन के लिए स्व घोषणा प्रारूप और अर्हित भवन पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा प्रमाणन प्रारूप 1क के साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थीय प्राधिकारी से निर्माण के लिए अनुमति हेतु आवेदन के अलावा पृथक् खाते में विनिर्दिष्ट फीस सहित आनलाइन प्रस्तुत करेगा । उसके पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी इसमें पर्यावरणीय शर्तों के

समावेशन के लिए निर्माण अनुमति जारी करेगा तथा आवेदन के साथ स्व घोषणा और प्रमाणन के आधार पर परियोजना आरंभ करने के लिए अनुमति देगा। भवन के निर्माण के समापन के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक अर्हित भवन पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा की गई संपरीक्षा के आधार पर आनलाइन आधारित प्ररूप 1क को अद्यतन करेगा तथा पुनरीक्षित अनुपालन परिवचन स्थानीय प्राधिकारी को देगा। 20,000 वर्ग मीटर से कम के भवनों के अनुपालन संबंधी कोई मुद्दा विद्यमान यांत्रिकी के दौरान स्थानीय प्राधिकारी और राज्य स्तर पर विचार किया जाएगा।

अन्य भवन प्रवर्ग (>20,000 वर्ग मीटर)

परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण मूल्यांकन के लिए विनिर्दिष्ट फीस सहित प्ररूप 1क में आनलाइन आवेदन तथा निर्माण अनुमति के लिए अतिरिक्त फीस प्रस्तुत करेगा। पर्यावरण मूल्यांकन के लिए फीस पृथक् खाते में जमा की जाएगी। पर्यावरण प्रकोष्ठ आवेदन पर कार्यवाही करेगा और उस स्थानीय प्राधिकारी में निर्माण अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के नेतृत्व वाली बैठक में प्रस्तुत करेगा। समिति परियोजना का मूल्यांकन करेगी और पर्यावरण शर्तों को निर्माण अनुमति में समावेशन के लिए शर्त रखेगा। समिति की सिफारिशों के पश्चात् निर्माण अनुमति और पर्यावरण अनापत्ति स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समेकित आरूप में जारी करेगा।

परियोजना प्रस्तावक अर्हित निर्माण पर्यावरण संपरीक्षक से संनिर्माण के समापन के पश्चात् लागू पर्यावरणीय शर्तें मानकों के लिए परियोजना में सतत् अनुपालन के प्रमाणपत्र और अनुपालन आंकड़ें प्रत्येक पांच वर्ष में पर्यावरण प्रकोष्ठ को निम्नलिखित मानकों पर विशेष केन्द्रित करते हुए प्रस्तुत करेगा :-

- (क) ऊर्जा प्रयोग (सभी ऊर्जा स्रोतों सहित)
- (ख) साइट पर पुनर्प्रयोग ऊर्जा स्रोतों से साइट पर उत्तपन की ऊर्जा
- (ग) साइट जल प्रयोग और अपशिष्ट जल उत्पन्न, उपचारित और पुनर्प्रयुक्त
- (घ) साइट पर पृथकीकृत और उपचारित अपशिष्ट
- (ङ) पौधारोपण और रखरखाव।

परियोजना के पूर्ण होने पर, प्रकोष्ठ पांच वर्षीय संपरीक्षा रिपोर्ट सहित परियोजना अनुपालन प्रास्थिति की अचावक जांच करेगा। राज्य सरकारें पर्यावरणीय शर्तों और मानकों के अनुपालन के लिए शास्तियां लगाने के लिए समुचित विधि अधिनियमित करेगी। प्रकोष्ठ स्थानीय प्राधिकारी शर्तें या मानकों के अनुपालन के लिए सुसंगत राज्य विधि के अधीन यथा लागू वित्तीय शास्तियों की सिफारिश करेगा। प्रकोष्ठ की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय प्राधिकारी सुसंगत राज्य विधि के अधीन शास्तियां अधिरोपित करेगा। असत्य घोषणा या प्रकाशन की दशा में प्रत्यानन निकाय को रिपोर्ट करेगा और स्थानीय निकाय अर्हित भवन पर्यावरण संपरीक्षकों को काली सूची में डाल देगा तथा मालिक और अर्हित निर्माण पर्यावरण संपरीक्षक पर वित्तीय शास्ति लगाएगा।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापन तथा प्रचालन की सहमति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति 1,50,000 वर्ग मीटर के लिए रिहायशी निर्माण हेतु अपेक्षित नहीं होगी,";

(II) अनुसूची में मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8.		भवन/योजना संनिर्माण/विकास योजना और नगरीय		
8(क)	भवन निर्माण और संनिर्माण परियोजना		निर्मित क्षेत्र का $\geq 20,000$ वर्ग मीटर और $\leq 1,50,000$ वर्ग मीटर	इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "निर्मित क्षेत्र" पद, सभी तलों को एक साथ मिलाकर निर्मित या आच्छादित क्षेत्र जिसके अंतर्गत उसका बेसमेंट भी है, जो भवन निर्माण तथा संनिर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित है। टिप्पण 1- परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अंतर्गत औद्योगिक शेड, विश्वविद्यालयों,

				<p>महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए छात्रावास,</p> <p>किंतु ऐसे भवन पोषणीय पर्यावरणीय प्रबंधन, ठोस और तरल तथा परिशिष्ट 14 में दी गई शर्तों को सुनिश्चित करेगी।</p> <p>टिप्पण 2: साधारण शर्तें लागू नहीं होंगी।</p> <p>टिप्पण 3: टिप्पण 1 में प्रदत्त छूट स्थानीय प्राधिकारी के स्तर पर भवन अनुमति सहित पर्यावरणीय मानकों के समाकलन के पश्चात् औद्योगिक शेड के लिए ही उपलब्ध होगी।</p>
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास योजनाएं	निर्मित क्षेत्र का $\geq 3,00,000$ वर्ग मीटर या आच्छादित क्षेत्र का ≥ 150 हेक्टेयर	निर्मित क्षेत्र का $\geq 1,50,000$ वर्ग मीटर और $< 3,00,000$ वर्ग मीटर या आच्छादित क्षेत्र का ≥ 50 हेक्टेयर और < 150 हेक्टेयर	टिप्पण: साधारण शर्तें लागू नहीं होंगी

[फा. सं. जे-19-2/2013-आईए-III(भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 को प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्वी संशोधन का.आ. 1737 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695 (अ) तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ) तारीख 10 दिसंबर, 2012, का.आ. 574 (अ) तारीख 13 मार्च, 2011, का.आ. 2896 (अ) तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674 (अ) तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559 (अ) तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731 (अ) तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1599 (अ) तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2600 (अ) तारीख 9 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252 (अ) तारीख 22 दिसंबर, 2014, का.आ. 382 (अ) तारीख 3 फरवरी, 2015 और का.आ. 811 (अ) तारीख 23 मार्च, 2015, का.आ. 996 (अ) तारीख 10 अप्रैल, 2015, का.आ. 1142 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015, का.आ. 1141 (अ) तारीख 29 अप्रैल, 2015, का.आ. 1834 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2015 और का.आ. 2572 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2015, का.आ. 141 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2016, का.आ. 190 (अ) तारीख 20 जनवरी, 2016, का.आ. 648 (अ) तारीख 3 मार्च, 2016 और का.आ. 2269 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा किए गए।

परिशिष्ट – XIV

भवनों तथा निर्माण के लिए पर्यावरणीय शर्तें

(श्रेणी-'I': 5,000 से लेकर 20,000 वर्ग मीटर से कम)

माध्यम	क्र.सं.	पर्यावरणीय शर्तें
स्थलाकृति तथा प्राकृतिक ड्रेनेज	1	जल के अबाधित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक ड्रेन प्रणाली का रखरखाव किया जाना चाहिए। किसी भी निर्माण कार्य को स्थल से होकर गुजरने वाले प्राकृतिक ड्रेनेज में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नम भूमि तथा जल निकायों पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ड्रेनेज पद्धति का रखरखाव करने तथा वर्षा जल संचयन के लिए चेक डैम, बायो-स्वेल, लैंडस्केप और अन्य वहनीय शहरी ड्रेनेज प्रणालियों की अनुमति है।
जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भू-जल स्तर में वृद्धि	2	जल-सक्षम उपस्करों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्षा जल संचयन संबंधी स्थानीय उपनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा। यदि स्थानीय उपनियम के उपबंध उपलब्ध न हों, तो शहरी विकास मंत्रालय के मॉडल भवन उपनियम, 2016 के अनुसार भण्डारण तथा रिचार्ज के लिए उचित उपबंध का अनुपालन किया जाएगा।

		वर्षा जल संचयन की एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें रिचार्ज बोर (प्रत्येक 5,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र पर न्यूनतम एक रिचार्ज) की सिफारिश की जाती है। संचित वर्षा जल के भण्डारण तथा पुनःप्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां भू-जल स्तर को बढ़ाना व्यवहार्य न हो, वर्षा जल का भण्डारण और पुनःप्रयोग किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना भू-जल नहीं निकाला जाएगा। सभी रिचार्ज को उथले जलभृत तक सीमित रखा जाना चाहिए।
	2 (क)	स्थानीय भवन उपनियमों में यथा अपेक्षित कम से कम 20% खुला स्थान प्रभावनीय होगा। कम से कम 50% ओपनिंग के साथ पेवर, पेवर ब्लॉकों, लैंडस्केप इत्यादि को प्रभावनीय तल समझा जाएगा।
अपशिष्ट प्रबंधन	3	<p>ठोस अपशिष्ट: अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक इकाई में तथा भू-तल पर अलग-अलग नम और शुष्क बिनों की व्यवस्था की जानी चाहिए।</p> <p>सीवेज: ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीवेज नेटवर्क नहीं है, वहां ऑनसाइट शोधन प्रणालियां संस्थापित की जानी चाहिए। लैंडस्केप से एकीकृत होने वाली प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक संभव हो शोधित बहिःस्राव का पुनःप्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरिक्त शोधित बहिःस्राव को सीपीसीबी प्रतिमानों के अनुपालन में निस्तारित किया जाएगा। सेप्टिक टैंकों सहित ऑनसाइट सीवेज शोधन से निकले गाद को शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा।</p> <p>ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 का अनुपालन किया जाएगा।</p>
ऊर्जा	4	<p>ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा।</p> <p>डिमांड लोड के 1% समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी।</p> <p>वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए अथवा स्थानीय भवन उपनियमों की आवश्यकतानुसार, जो भी अधिक हो, सोलर वाटर हीटिंग की व्यवस्था की जाएगी। आवासीय भवनों के लिए भी यथासंभव अपनी गर्म जल मांग की पूर्ति हेतु सोलर वाटर हीटिंग की सिफारिश की जाती है।</p> <p>भवन डिजायनों में पैसिव सोलर डिजायन की संकल्पना शामिल की जाएगी जिसमें डिजायन के तत्वों जैसे भवन अभिमुखीकरण, लैंडस्केपिंग, दक्ष भवन एन्वेलप, समुचित खिड़कियों की व्यवस्था, दिन में अधिक प्रकाश करने की व्यवस्था में सुधार और थर्मल मास इत्यादि का प्रयोग करके भवनों में ऊर्जा खपत को न्यूनतम किया जाता है। दीवारें, खिड़कियां और छत के यू-वॉल्व ईसीबीसी विशिष्टियों के अनुसार होंगे।</p>
वायु गुणवत्ता तथा शोर	5	<p>भवन और साथ ही स्थल के लिए धूल, धुआं एवं अन्य वायु प्रदूषण निवारण के उपाय किए जाएंगे। इन उपायों में निर्माणाधीन भवन, स्थल के चारों ओर धूल/धूल रोकने वाली दीवारों का निर्माण (कम से कम 3 मीटर की ऊंचाई तक) के लिए आवरण में शामिल हो सकेंगे। प्लाटिक/तारपोलिन स्थल से कचरा उठाने के साथ-साथ बालू, सीमेंट, मूर्म में चलती हुई गाड़ियां तथा अन्य निर्माण सामग्रियां धूल प्रदूषण का कारण हो सकती हैं।</p> <p>साइट पर बालू, मूर्म, बिखरी मिट्टी, सीमेंट भंडार को उचित तरीके से ढक कर रखा जाएगा जिससे कि धूल प्रदूषण को रोका जा सके।</p> <p>पिसाई तथा पत्थर कटाई के लिए वेट जेट का प्रबंध किया जाएगा। धूल को दबाने के लिए</p>

		<p>बिना पटरी बिछा हुआ धरातल तथा बिखरी मिट्टी पर उचित तरीके से पानी का छिड़काव किया जाएगा।</p> <p>निर्माण तथा विध्वंस सारे मलबे को उचित तरीके से निपटान से पहले साइट के पास इकट्ठा किया जाएगा (तथा सड़के के किनारे ढेर या बाहर खुली जगह में इकट्ठा नहीं) सभी विध्वंस तथा निर्माण अपशिष्ट को निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधित होगा। निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले सभी कामगारों तथा निर्माण सामग्री की लोडिंग अनलोडिंग में शामिल, निर्माण सामग्री की ढुलाई तथा निर्माण के कचरे या धूल प्रदूषण के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति को डस्ट मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। आंतरिक वायु गुणवत्ता के लिए भारत के राष्ट्रीय भवन कोड के अनुसार वातायन के प्रावधान तैयार किए जाएंगे।</p>
	5(क)	डीजी सेट का स्थान निर्धारण तथा निकास पाइप की ऊंचाई सीपीसीबी मानदंडों के प्रावधानों के अनुसार होगा।
हरित क्षेत्र	6	प्रति 80 वर्ग मीटर की भूमि के लिए कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विद्यमान पेड़ों की गिनती की जाएगी। देशीय जाति के पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
	6(क)	जहां पेड़ों की कटाई आवश्यक हो, 1:3 के अनुपात में प्रतिपूरक वृक्षारोपण अर्थात् प्रत्येक एक पेड़ की कटाई के लिए 3 पौधों को लगाना तथा उनका रख-रखाव करना होगा।

(श्रेणी '2': 20,000 वर्ग मीटर से लेकर 50,000 से कम)

माध्यम	क्रम.सं.	पर्यावरणीय शर्तें
स्थलाकृति तथा प्राकृतिक जल निकास	1	<p>जल की अबाधित धारा सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक जल निकास प्रणाली का प्रबंध होना चाहिए। साइट के माध्यम से प्राकृतिक जल निकास को अवरोध करने के लिए निर्माण की अनुमति नहीं होगी। नमभूमि और जल निकायों पर निर्माण की अनुमति नहीं होगी। जल निकास पैटर्न तथा वर्षा जल संचयन के लिए चेक डैम, बायो-स्वाल्स, लैंडस्केप तथा अन्य धारणीय शहरी जल निकास प्रणालियों (एसयूडीएस) की अनुमति होगी।</p> <p>जहां तक संभव हो सके, भवनों की डिजाइन में प्राकृतिक स्थलाकृति का पालन किया जाएगा। कम से कम कटाई तथा भराई होनी चाहिए।</p>
जल संरक्षण, वर्षा जल सिंचाई तथा भूमि जल को रिचार्ज करना	2	<p>जल संचयन, जल क्षमता और संरक्षण के लिए एक पूर्ण योजना तैयार की जाए।</p> <p>न्यून फिक्चर या सेंसरों वाले जल क्षमता वाले उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।</p> <p>वर्षा संचयन के संबंध में स्थानीय उप नियम, उपबंधों का पालन किया जाएगा। अगर स्थानीय उप नियम उपलब्ध नहीं है तो शहरी विकास मंत्रालय का मॉडल भवन उप नियम, 2016 के अनुसार भंडारण तथा रिचार्ज के लिए पर्याप्त प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।</p> <p>वर्षा जल संचयन योजना का डिजाइन बनाने की आवश्यकता है जहां 5000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में कम से कम एक रिचार्ज बोर हो तथा कम से कम कुल एक दिन के शुद्ध जल के प्रबंधन की भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी। उन क्षेत्रों, जहां भूमिगत जल को रिचार्ज करना संभव नहीं है, में वर्षा जल संचयन चाहिए तथा पुनः उपयोग के लिए भंडारण किया जाएगा। भूमिगत जल को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं निकाला जाएगा।</p> <p>सभी रिचार्ज सीमित उथले जलभृत तक सीमित होनी चाहिए।</p>
	2 (क)	<p>स्थानीय भवन उप-नियमों द्वारा यथाअपेक्षित खुले स्थानों का कम से कम 20% भाग भेद्य होगा। न्यूनतम 50% खाली जगह, भूदृश्य आदि सहित हरित खंडजों, खंडज प्रखंड के उपयोग सहित यथा प्रवेश्य धरातल के रूप में विचार किया जाएगा।</p>
अपशिष्ट प्रबंधन	3	<p>ठोस अपशिष्ट: प्रत्येक इकाई में और भू तल पर पृथक-पृथक गीले और सूखे कचरे के डिब्बे, अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किए जाएंगे।</p> <p>मलजल: अपशिष्ट 100% अपशिष्ट जल के शोधन की स्थल पर मलजल शोधन क्षमता संस्थापित की</p>

		<p>जानी है। शोधित अपशिष्ट जल को स्थल पर भूदृश्य, फलशिंग, कूलिंग टावर और अन्य प्रयोजनार्थ पुनःप्रयोग किया जाएगा। अतिरिक्त शोधित जल को सीपीसीबी मानकों के अनुसार छोड़ा जाएगा। प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा।</p> <p>सेप्टिक टैंकों सहित स्थल पर (ऑन साइट) शोधन से अवमल का मल-निर्यास और मलजल शोधन प्रणाली, 2013 पर शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ), के मैनुअल के अनुसार संग्रहण, ढुलाई और निपटान किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।</p>
	3 (क)	सभी गैर-जैवक्रमणीय अपशिष्ट प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपा जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ लिखित में गठजोड़ किया जाना चाहिए।
	3 (ख)	जैविक अपशिष्ट कम्पोस्ट/0.3 कि./प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन की न्यूनतम क्षमता वाला वर्मिकल्चर/पिट संस्थापित किया जाना चाहिए।
ऊर्जा	4	<p>ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में जिन भवनों ने अपने स्वयं ईसीबीसी अधिसूचित किए हैं, वे भवन राज्य ईसीबीसी का अनुपालन करेंगे।</p> <p>बाहरी क्षेत्र और साझा क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था एलईडी की होगी।</p> <p>पैसिव सौर डिजाइन की संकल्पना, जिसमें भवनोन्मुख, भू-दृश्य निर्माण, कौशलपूर्ण भवन आवरण, उचित गवाक्षीकरण, दिन में उन्नत प्रकाश व्यवस्था डिजाइन और ताप विद्युत मास आदि का उपयोग करके भवनों में ऊर्जा उपभोग न्यूनतम किया जाता है, भवन डिजाइन में समावेशित किया जाएगा। दीवार, खिड़की और रूफ-यू-वैल्यूज, ईसीबीसी विनिर्देशों अनुसार होनी चाहिए।</p>
	4 (क)	भार की मांग के 1% के बराबर विद्युत उत्पादन अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उप-नियमों की अपेक्षानुसार जो भी अधिक हो, को पूरा करने के लिए सौर, पवन अथवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित की जाएगी।
	4 (ख)	वाणिज्यिक और संस्थागत भवनों की गर्म जल की 20% मांग अथवा स्थानीय भवन उप-नियमों के यथा अपेक्षा अनुसार, जो भी अधिक हो, को पूरा करने के लिए सौर जल तापक प्रदान किए जाएंगे। आवासीय भवनों को भी यथासंभव सौर जल हीटर्स से अपनी गर्मपानी की मांग पूरा करने के लिए सुझाव दिया गया है।
	4 (ग)	<p>निर्माण सामग्री की मात्रा के कम से कम 20% मात्रा हेतु ईटों, प्रखंडों और अन्य निर्माण सामग्रियों में पर्यावरण अनुकूलन सामग्री का उपयोग करना अपेक्षित होगा। इनके फ्लाई ऐश ईटे, खोखली (हौलो) ईटे, एएसी, फ्लाई ऐश चूनापत्थर, जिप्सम प्रखंड, कम्प्रेस्ड मृदा प्रखंड और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्रियां शामिल हैं।</p> <p>फ्लाई ऐश को समय-समय पर यथा संशोधित सितम्बर, 1999 की फ्लाई ऐश अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार निर्माण में भवन सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए।</p>
वायु गुणवत्ता और ध्वनि	5	<p>भवन के साथ-साथ निर्माण स्थल के लिए धूल कण, धुंध और अन्य वायु प्रदूषण उपशमन उपाय अपनाएं जाएंगे। इन उपायों में निर्माणाधीन भवनों के लिए स्क्रीन, निर्माण स्थल के चारों ओर सतत धूलकण/पवन को मंद करने के लिए दीवारों (कम से कम 3 मीटर ऊँची) का निर्माण शामिल हैं। निर्माण स्थल में बालू, सीमेंट, लोहबान और अन्य निर्माण सामग्रियां, जिनके कारण स्थल पर धूल प्रदूषण उत्पन्न होता है, लाने वाले और निर्माण स्थल से डेबरी ले जाने वाले वाहनों के लिए प्लास्टिक/तिरपाल की शीट कवर प्रदान किए जाने चाहिए।</p> <p>स्थल पर भण्डारण किए हुए बालू, लोहबान, खुली मृदा, सीमेंट को पर्याप्त रूप से ढका होना चाहिए ताकि धूलकण से प्रदूषण की रोकथाम की जा सके।</p> <p>निर्माण सामग्री की पिसाई और पत्थरों की कटाई के लिए वेटजेट प्रदान किए जाएंगे।</p> <p>निर्माण और विध्वंस का समस्त कचरा उचित ढंग से निपटान किए जाने से पूर्व स्थल पर ही रखा जाएगा (सड़क अथवा बाहर खुले स्थान पर ढेर नहीं लगाया जाएगा)। समस्त विध्वंस और निर्माण अपशिष्ट का प्रबंधन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।</p>

		निर्माण स्थल पर कार्यरत तथा निर्माण सामग्री और निर्माण कचरे को लादने, उतराने, ढुलाई अथवा धूल प्रदूषण वाले किसी क्षेत्र में कार्यरत सभी मजदूरों को डस्ट मास्क उपलब्ध कराए जाएं। भीतरी वायु गुणवत्ता के संबंध में भारत के राष्ट्रीय भवन क्रोड के अनुसार वायुसंचार प्रावधान किए जाएं।
	5(क)	डीजी सेट का स्थान और निकास नली की ऊँचाई सीपीसीवी मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
हरित आवरण	6	प्रति 80 वर्गफुट भूमि के लिए कम से कम एक वृक्ष लगाया जाना चाहिए और उसकी देख-रेख की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विद्यमान वृक्षों की गणना की जाएगी। स्थानिक प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
	6(क)	जहाँ वृक्षों को काटे जाने की आवश्यकता है, 1:3 (अर्थात् काटे गए प्रत्येक 1 वृक्ष के लिए 3 वृक्षों का रोपण) के अनुपात में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाए और उसका रख-रखाव किया जाए।
ऊपरी मृदा का परिरक्षण और पुनः उपयोग	7	भवनों, सड़कों, पेवड क्षेत्रों और बाह्य सेवाओं हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों से ऊपरी मृदा को 20 सेमी. की गहराई तक खोदा जाए। इसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में उपयुक्त तरीके से संचित किया जाए तथा स्थल पर प्रस्तावित पेड़-पौधों के रोपण के दौरान पुनः उपयोग किया जाए।
परिवहन	8	एमओयूडी सर्वोत्तम पद्धतियां दिशा-निर्देश(यूआरडीपीएफआई) के अनुसार, एक व्यापक मोबिलिटी योजना बनाई जाए ताकि मोटर-सज्जित, गैर-मोटर-सज्जित, सार्वजनिक और निजी नेटवर्कों को शामिल किया जा सके। सड़क का डिजाइन पर्यावरण, और उपयोक्ताओं की सुरक्षा को पर्याप्त ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। सड़क प्रणाली का डिजाइन इन मूलभूत मापदंडों के अनुसार बनाया जा सकता है। वाहनीय और पैदल यातायात के उचित पृथक्करण से सड़कों का अनुक्रम। यातायात शामक उपाय। प्रवेश और निकासी बिंदुओं का उचित डिजाइन। स्थानीय विनियम के अनुसार पार्किंग मानक।

(श्रेणी '3' : 50000 से 150000 वर्ग मीटर)

माध्यम	क्र.सं.	पर्यावरणीय स्थिति
स्थलाकृति और प्राकृतिक निकासी	1	जल का अबाधित बहाव सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक निकासी प्रणाली का रख-रखाव किया जाना चाहिए। ऐसे किसी निर्माण की अनुमति न दी जाए जिससे कि स्थल के माध्यम से प्राकृतिक निकासी बाधित हो। आर्द्रभूमि और जल निकायों पर किसी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है। निकासी पैटर्न को बनाए रखने तथा वर्षा जल संचयन के लिए चक्र बांध, बाँयो.स्वेलस, भू-दृश्य, और अन्य सतत शहरी निकासी प्रणालियां (एसयूडीएस) अनुमत हैं। भवनों का डिजाइन, जहाँ तक संभव हो, प्राकृतिक स्थलाकृति के अनुसार बनाया जाना चाहिए। पेड़ों को काटना और गिराना न्यूनतम होना चाहिए।
जल संरक्षण-वर्षा जल संचयन और भू जल रिचार्ज	2	वर्षा जल संचयन, जल के गुणवत्ता तथा संरक्षण के लिए एक पूर्ण योजना बनाई जाए। वर्षा जल संचयन के संबंध में स्थानीय उपविधि का पालन किया जाए। यदि स्थानीय उपविधि उपलब्ध न हों, तो शहरी विकास मंत्रालय के मॉडल भवन उपविधि, 2016 के अनुसार भंडारण और रिचार्ज संबंधी उपयुक्त प्रावधानों का पालन किया जाए। एक वर्षा जल संचयन योजना डिजाइन किए जाने की आवश्यकता है जहाँ निर्मित क्षेत्र के प्रति 5,000 वर्ग मीटर न्यूनतम एक रिचार्ज बोर और कुल ताजा जल आवश्यकता की न्यूनतम एक दिन की भंडारण क्षमता का रिचार्ज बोर प्रदान किया जाए। ऐसे क्षेत्र जहाँ भूजल रिचार्ज व्यवहार्य नहीं है, वहाँ वर्षा जल का संचयन और पुनः उपयोग हेतु भंडारण किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिए बिना भूजल न निकाला जाए।

		सभी रिचार्ज ऊपरी जलभृत एक सीमित होने चाहिए।
	2 (क)	स्थानीय भवन उप-नियमों द्वारा का यथा अपेक्षित खुले स्थान कम से कम 20% प्रवेश्य होगा। कम से कम 50% खुले स्थान वाले ग्रास पेवर, पेवर ब्लॉक, भू-दृश्य इत्यादि को प्रवेश्य सतह माना जाएगा।
	2 (ख)	जल किफायती उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। लो-फ्लो फिक्सरों अथवा सेंसरों का प्रयोग जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाए।
	2 (ग)	दोहरी प्लंबिंग प्रणाली के प्रयोग द्वारा भूरे और काले पानी को पृथक किया जाए। सिंगल स्टेक प्रणाली के मामले में दोहरी प्लंबिंग प्रणाली द्वारा फ्लशिंग के लिए अलग पुनर्संचरण लाइनें बनाई जायेंगी।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	3	ठोस अपशिष्ट: अपशिष्ट के अलग-अलग करने को आसान बनाने के लिए प्रत्येक इकाई और भूतल पर अलग-अलग गीले और सूखे कूड़े दान उपलब्ध कराए जाएं। ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016, और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।
	3 (क)	सभी गैर जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट को प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के हवाले कर दिया जाएगा जिसके लिए प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ लिखित समझौता किया जाएगा।
	3 (ख)	न्यूनतम 0.3 किग्रा/व्यक्ति/दिन की क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कम्पोस्टर/वर्मीकल्चर गड्डे बनाए जायेंगे।
मल-जल शोधन संयंत्र	4	स्थल पर 100% अपशिष्ट जल शोधन क्षमता के मल-जल शोधन की अवस्थापना किया जाना। शोधित मल-जल का पुनर्प्रयोग स्थल पर लैंड-स्केप, फ्लशिंग, कूलिंग टावर और अन्य अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए किया जाए। अतिरिक्त शोधित जल को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार बहाया जाएगा। प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सेप्टिक टैंकों सहित साइट पर मल-जल शोधन से उत्पन्न तलछट को एकत्र किया जाएगा और उसे शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और मल-जल एवं मल-जल शोधन संयंत्र, 2013 संबंधी पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल के अनुसार ढोकर निपटान किया जाएगा।
ऊर्जा	5	ऊर्जा दक्षता व्यरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिन राज्यों ने अपना स्वयं का ईसीबीसी अधिसूचित किया है, भवन अभिकल्पन में राज्य ईसीबीसी का अनुपालन करेंगे। प्रकाश व्यवस्था बाहरी और कॉमन एरिया में एलईडी की होगी। भवन अभिकल्पन में भवन अनुस्थापन, भू-दृश्यीकरण, प्रभावी भवन विकास, खिड़कियों की समुचित व्यवस्था, जिनमें प्रकाश बढ़ाने वाला अभिकल्पन और थर्मल मास इत्यादि जैसे अभिकल्पन तत्वों का प्रयोग करके भवन में न्यूनतम ऊर्जा खपत वाले पैसिव सोलर अभिकल्पन की संकल्पना को शामिल किया जाएगा। दीवार, खिड़की और छत यू-वैल्यूज़ ईसीबीसी विनिर्देशों के अनुसार होंगे।
	5 (क)	सौर, पवन या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था ताकि मांग भार या राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उप-नियमों या जो भी अधिक हो, के अनुसार 1% के बराबर विद्युत उत्पादन पूरा किया जा सके।
	5 (ख)	व्यावसायिक और सांस्थानिक भवनों की 20% गर्म पानी की मांग को पूरा करने या स्थानीय भवन उप-नियमों की आवश्यकता, जो भी अधिक हो, के अनुसार सोलर वाटर हीटिंग उपलब्ध कराई जाएगी। आवासीय भवनों को भी, जहां तक संभव हो, अपनी गर्म पानी की मांग को सोलर वाटर से पूरा करने की सिफारिश की जाती है।
	5 (ग)	ईटों, ब्लॉक्स और अन्य निर्माण सामग्री में कम से कम 20% पर्यावरण अनुकूल सामग्री के प्रयोग की आवश्यकता होगी। इसमें फ्लाई ऐश, ईटें, हॉलों ईटों, एएसी, फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम ब्लॉकस,

		<p>कम्प्रेस्ड अर्थ बलॉक्स और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री शामिल होगी।</p> <p>समय-समय पर यथा संशोधित सितंबर, 1999 की फ्लाइ ऐश अधिसूचना के अनुसार निर्माण में भवन सामग्री के रूप में फ्लाइ ऐश का प्रयोग किया जाना चाहिए।</p>
जल गुणवत्ता और ध्वनि	6	<p>भवन और स्थान में धूल, धुआँ और अन्य वायु प्रदूषण निवारक उपाय किए जाएं। इन उपायों में निर्माणाधीन भवन के लिए स्क्रीन, स्थल के चारों ओर सतत रूप से धूल/हवा रोकने वाली दीवारें कम से कम 3 मीटर ऊंचाई की) शामिल हैं। स्थल पर रेत, सीमेंट, लोहबान और अन्य निर्माण सामग्री, जो कि धूल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, के साथ-साथ स्थल से मलबे को बाहर ले जाने वाले वाहनों के लिए प्लास्टिक/तिरपाल के शीट कवर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रयुक्त वाहनों के पहियों की धुलाई की जाएगी।</p> <p>स्थल पर भण्डारित रेत, लोहबान, खुली मृदा, सीमेंट को अच्छी प्रकार से ढका जाएगा ताकि धूल प्रदूषण को रोका जा सके।</p> <p>पिसाई और पत्थर कटाई के लिए वेट जेट उपलब्ध कराया जाएगा। धूल को दबाने के लिए कच्ची सतहों और खुली मृदा पर पर्याप्त जल छिड़काव किया जाएगा।</p> <p>सभी निर्माण और विध्वंस मलबे के समुचित निपटान (बाहर सड़कों या खुले स्थानों पर ढेर नहीं लगाया जाएगा) से पहले, स्थल पर उनका भण्डारण किया जाएगा। सभी विध्वंस और निर्माण अपशिष्ट का, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधन किया जाएगा।</p> <p>निर्माण स्थल पर कार्यरत और निर्माण सामग्री और निर्माण मलबे की लदाई, उतराई और ढुलाई में शामिल अथवा धूल प्रदूषण से युक्त किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी कामगारों को धूल रोधी मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे।</p> <p>भीतरी वायु गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय भारतीय भवन संहिता के अनुसार वातायान-व्यवस्था के प्रावधान।</p>
	6(क)	डीजी सेट का स्थान और निकास पाइप की ऊंचाई, सीपीसीबी मापदंडों के उपबंधों के अनुसार होगी।
हरित आवरण	7	प्रत्येक 80 वर्ग मीटर भूमि के लिए न्यूनतम 1 पेड़ लगाया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा। इस प्रयोजन से मौजूदा पेड़ों की गिनती की जाएगी। स्थानिक प्रजातियों लगाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
	7(क)	जहां पर पेड़ों को काटे जाने की आवश्यकता है वहां पर 1:3 के अनुपात (अर्थात् काटे गए प्रत्येक 1 पेड़ के लिए 3 पेड़ लगाना) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा और रखरखाव किया जाएगा।
ऊपरी मृदा परिरक्षण और पुनर्उपयोग	8	भवनों, सड़कों, पक्के क्षेत्रों और बाहरी सेवाओं के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों से 20 सेमी की गहराई तक ऊपरी मृदा को खोदा जाना चाहिए। इसका निर्धारित क्षेत्रों में समुचित ढंग से भण्डारण किया जाना चाहिए और स्थल पर प्रस्तावित वनस्पति के रोपण के दौरान इसका पुनर्उपयोग किया जाएगा।
परिवहन	9	<p>शहरी विकास मंत्रालय की उत्तम प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों (यूआरडीपीएफआई) के अनुसार मोटरयुक्त, गैर-मोटरयुक्त, सार्वजनिक और निजी तंत्रों को शामिल करने के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना तैयार की जाएगी।</p> <p>सड़कों को पर्यावरण और प्रयोक्ताओं की सुरक्षा पर अपेक्षित विचार करते हुए अभिकल्पित किया जाना चाहिए। सड़क प्रणाली को इन आधारभूत मानदंडों के साथ अभिकल्पित किया जा सकता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वाहनीय और पैदल-पथ यातायात के उचित पृथक्करण के साथ सड़कों का वर्गीकरण 2. यातायात को सुचारू रखने के उपाय 3. प्रवेश और निकास बिंदुओं का उचित अभिकल्प 4. स्थानीय विनियमन के अनुसार पार्किंग मापदंड

पर्यावरण प्रबंधन योजना	10	उपरोक्त मद सं. 1 से 9 में विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार और क्रियान्वित की जाएगी। ईएमपी को क्रियान्वित करने के लिए परिभाषित क्रियाकलापों और उत्तरदायित्व के साथ एक समर्पित पर्यावरण निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। यह पर्यावरणीय प्रकोष्ठ सुनिश्चित करेगा कि मलजल शोधन संयंत्र, भू-दृश्य निर्माण, वर्षा-जल संचयन, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, जल दक्षता और संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसी पर्यावरण अवसंरचना प्रचालनारत है और अपेक्षित मानकों को पूरा करती है। पर्यावरणीय प्रकोष्ठ, पर्यावरण निगरानी और पर्यावरण अवसंरचना से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव भी करेगा।
------------------------	----	---

परिशिष्ट-XV

पर्यावरणीय लेखा परीक्षकों (योग्य भवन लेखा परीक्षक) की मान्यता

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) योग्य अभिकरणों के माध्यम से योग्य भवन पर्यावरण लेखा परीक्षकों (क्यूबीईए) को मान्यता देगा। योग्य भवन पर्यावरण लेखा परीक्षक फर्म/संगठन अथवा वैयक्तिक विशेषज्ञ हो सकते हैं, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। मंत्रालय, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संगठन के माध्यम से मान्यता की इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करेगा। भारतीय हरित भवन परिषद, उर्जा दक्षता ब्यूरो इत्यादि जैसे संगठन भी मान्यता देने, प्रशिक्षण और नवीकरण की प्रक्रिया से जोड़े जा सकते हैं। भवन क्षेत्र के लिए क्यूसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय परामर्शी क्यूबीईए के रूप में योग्य होंगे। क्यूबीईए निम्नलिखित मानदंड पूरा करेंगे। मान्यता देने वाला प्राधिकरण इन मानदंडों का सुधार कर सकता है।

लेखा परीक्षक की योग्यताएं :

क. शिक्षा: वास्तुकार (डिग्री अथवा डिप्लोमा), नगर नियोजक (डिग्री), सिविल इंजीनियर/मैकनिकल इंजीनियर (डिग्री अथवा डिप्लोमा), पर्यावरणीय विज्ञान में स्नातकोत्तर अथवा मान्यता की स्कीम के अनुसार कोई अन्य योग्यता

प्रशिक्षण :

ख. प्रत्यायन निकाय अथवा उनके अनुमोदित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह मान्यता की स्कीम के अनुसार होगा।

अनुभव :

ग. संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा क्यूसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त भवन और पर्यावरण प्रभाव आकलन परामर्शदाता अथवा मान्यता की स्कीम के अनुसार किसी अन्य प्रकार का अनुभव मानदंड।

अवसंरचना एवं उपकरण :

घ. मान्यता की स्कीम के अनुसार

नवीकरण:

ड. प्रत्यायन 5 वर्षों के लिए मान्य होगा और प्रत्यायन स्कीम के अंतर्गत विकसित प्रक्रिया के अनुसार नवीकृत किया जाएगा।

उत्तरदायित्व/शिकायत निवारण कार्यतंत्र: क्यूबीईएएस के कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी शिकायत प्रत्यायन निकाय को की जाएगी। प्रत्यायन निकाय शिकायत पर विचार करेगा और काली सूची में डालने अथवा व्यापक सार्वजनिक सूचना के साथ प्रत्यायन को रद्द करने सहित उपयुक्त कार्यवाही करेगा। यह दण्ड देने और काली सूची में डालने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के अलावा होगा। विशिष्ट शिकायत अथवा फीडबैक के मामले में मंत्रालय भी इस प्रकार की कार्यवाही कर सकता है।

परिशिष्ट-XVI

स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर पर्यावरणीय प्रकोष्ठ:

भवनों में पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन और मानीटरी को सहायता देने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर पर्यावरणीय प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। यह प्रकोष्ठ अपने क्षेत्राधिकार के तहत पर्यावरणीय आयोजना और क्षमता निर्माण में सहायता भी प्रदान करेगा। इस प्रकोष्ठ के उत्तरदायित्व, इस अधिसूचना के कार्यान्वयन की मानीटरी करना और तीसरे-पक्षकार की लेखा-परीक्षा प्रक्रिया का अनुरक्षण करना है। यह प्रकोष्ठ स्थानीय प्राधिकरण के तहत संचालित होगा।

प्रकोष्ठ का संघटन :

इस प्रकोष्ठ में निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम 3 समर्पित व्यक्ति शामिल होंगे:

- क. अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस और द्रव्य)
- ख. जल संरक्षण और प्रबंधन
- ग. निर्माण सामग्रियों सहित संसाधन की कार्यकुशलता
- घ. ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा
- च. वायु गुणवत्ता प्रबंधन सहित पर्यावरणीय आयोजना
- छ. परिवहन आयोजना और प्रबंधन

यह प्रकोष्ठ समर्पित विशेषज्ञों की आवश्यकता और पृष्ठभूमि के अनुसार कम से कम दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करेगा। स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर मौजूदा पर्यावरणीय प्रकोष्ठों को सह-योजित और इस प्रकोष्ठ के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता:

पर्यावरणीय शर्तों के समाकलन और इसकी मॉनीटरिंग के लिए निर्माण अनुमति हेतु कार्यवाही शुल्क के साथ अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। स्थानीय प्राधिकरण समय-समय पर इस अतिरिक्त शुल्क को निर्धारित और संशोधित कर सकता है। इस शुल्क की धनराशि, एक पृथक बैंक खाते में जमा किया जाएगा और विशेषज्ञों के वेतन/पारिश्रमिक की आवश्यकता को पूरा करने और ऑनलाइन प्रार्थना पत्र की प्रणाली को जारी रखने, सत्यापन और पर्यावरणीय प्रकोष्ठ के लिये उपयोग में लाया जाएगा।

प्रकोष्ठ के कार्य

1. यह प्रकोष्ठ अपने क्षेत्राधिकार में उस क्षेत्र के पर्यावरण सरोकारों का मूल्यांकन और आकलन करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां निर्माण कार्यकलाप करना प्रस्तावित है। यह प्रकोष्ठ अपेक्षाओं के अनुसार अतिरिक्त पर्यावरणीय शर्तें विकसित कर सकता है और शर्तों का प्रस्ताव रख सकता है। ये शर्तें क्षेत्र विशिष्ट हो सकती हैं तथा समय-समय पर पहले से अधिसूचित की जाएंगी। ये अतिरिक्त शर्तें परामर्श की यथा प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुमोदित की जाएंगी। ये पर्यावरणीय शर्तें अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा निर्माण अनुमति में समेकित की जाएंगी।
2. आवेदन और शुल्क के भुगतान के लिए एक ऑन लाइन प्रणाली बनाना तथा उसकी देख-रेख करना। यह प्रकोष्ठ प्राप्त सभी आवेदनों, अनुमोदित परियोजनाओं, अनुपालन लेखापरीक्षण रिपोर्ट, किए गए औचक निरीक्षणों का एक आनलाइन डाटाबेस बनाएगा। यह प्रकोष्ठ परियोजना द्वारा पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की लोगों द्वारा संवीक्षा के लिए अर्हता-प्राप्त निर्माण पर्यावरण लेखा-परीक्षकों द्वारा दर्ज लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के स्व-प्रमाणीकरण और अनुपालन सहित परियोजना व्यौरों का सार्वजनिक प्रकटन के लिए एक पोर्टल बनाएगा।
3. अर्हता-प्राप्त निर्माण लेखा-परीक्षकों द्वारा कराई गई पर्यावरणीय लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के कार्य की निगरानी करेगा।
4. यह प्रकोष्ठ आवेदनों की समीक्षा करेगा; स्थानीय प्राधिकरणों को आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिन के अंदर अतिरिक्त पर्यावरणीय शर्तों, यदि अपेक्षित हो तो, को अंतिम रूप देगा।
5. यह प्रकोष्ठ क्यूबीए के प्रमाणीकरण, पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन और पंच वर्षीय लेखा रिपोर्ट के लिए स्थल पर जांच करने के लिए परियोजनाओं का जोखिम आधारित औचक चयन अंगीकृत करेगा।
6. यह प्रकोष्ठ परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय शर्तों के गैर-अनुपालन के लिए वित्तीय अर्थदंड के लिए स्थानीय प्राधिकरण को सिफारिश करेगा।
7. यह प्रकोष्ठ किसी भी अर्हता-प्राप्त निर्माण पर्यावरण लेखा-परीक्षकों के विरुद्ध, यदि उनके कार्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो, प्रत्यायोजन निकाय और स्थानीय प्राधिकरण को सिफारिश करेगा।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

S.O. 3999(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 and clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the said Ministry has received suggestions for ensuring Ease of Doing Responsible Business; and streamlining the permissions for buildings and construction sector which is important for providing houses and for this purpose the scheme of Housing for all by 2022 with an objective of making available affordable housing to weaker sections in urban area has ambitious target;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas, a draft notification for making amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published, vide number S.O.1595 (E) dated the 29th April 2016, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of said notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:-

In the said Notification,-

(I) after paragraph 13, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“14. Integration of environmental condition in building bye-laws.-

(1) The integrated environmental conditions with the building permission being granted by the local authorities and the construction of buildings as per the size shall adhere to the objectives and monitorable environmental conditions as given at Appendix-XIV.

(2) The States adopting the objectives and monitorable environmental conditions referred to in subparagraph (1), in the building bye-laws and relevant State laws and incorporating these conditions in the approvals given for building construction making it legally enforceable shall not require a separate environmental clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for individual buildings.

(3) The States may forward the proposed changes in their bye-laws and rules to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, who in turn will examine the said draft bye-laws and rules and convey the concurrence to the State Governments.

(4) When the State Governments notifies the bye-laws and rules concurred by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Central Government may issue an order stating that no separate environmental clearance is required for buildings to be constructed in the States or local authority areas.

- (5) The local authorities like Development Authorities, Municipal Corporations, may certify the compliance of the environmental conditions prior to issuance of Completion Certificate, as applicable as per the requirements stipulated for such buildings based on the recommendation of the Environmental Cell constituted in the local authority.
- (6) The State Governments where bye-laws or rules are not framed may continue to follow the existing procedure of appraisal for individual projects and grant of Environmental Clearance for buildings and constructions as per the provisions laid down in this notification.
- (7) For the purpose of certification regarding incorporation of environmental conditions in buildings, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may empanel through competent agencies, the Qualified Building Environment Auditors (QBEAs) to assess and certify the building projects, as per the requirements of this notification and the procedure for accreditation of Qualified Building Auditors and their role as given at Appendix-XV.
- (8) In order to implement the integration of environmental condition in building bye-laws, the State Governments or Local Authorities may constitute the Environment Cell (herein after called as Cell), for compliance and monitoring and to ensure environmental planning within their jurisdiction.
- (9) The Cell shall monitor the implementation of the bye-laws and rules framed for Integration of environmental conditions for construction of building and the Cell may also allow the third party auditing process for oversight, if any.
- (10) The Cell shall function under the administrative control of the Local Authorities.
- (11) The composition and functions of the Cell are given at Appendix-XVI.
- (12) The Local Authorities while integrating the environmental concerns in the building bye-laws, as per their size of the project, shall follow the procedure, as given below:

BUILDINGS CATEGORY '1' (5,000 to < 20,000 Square meters)

A Self declaration Form to comply with the environmental conditions (Appendix XIV) along with Form 1A and certification by the Qualified Building Environment Auditor to be submitted online by the project proponent besides application for building permission to the local authority along with the specified fee in separate accounts. Thereafter, the local authority may issue the building permission incorporating the environmental conditions in it and allow the project to start based on the self declaration and certification along with the application. After completion of the construction of the building, the project proponent may update Form 1A online based on audit done by the Qualified Building Environment Auditor and shall furnish the revised compliance undertaking to the local authority. Any non-compliance issues in buildings less than 20,000 square meters shall be dealt at the level of local body and the State through existing mechanism.

OTHER BUILDINGS CATEGORIES (\geq 20,000 Square meters)

The project proponent may submit online application in Form 1 A alongwith specified fee for environmental appraisal and additional fee for building permission. The fee for environmental appraisal will be deposited in a separate account. The Environment Cell will process the application and present it in the meeting of the Committee headed by the authority competent to give building permission in that local authority. The Committee will appraise the project and stipulate the environmental conditions to be integrated in the building permission. After recommendations of the Committee, the building permission and environmental clearance will be issued in an integrated format by the local authority.

The project proponent shall submit Performance Data and Certificate of Continued Compliance of the project for the environmental conditions parameters applicable after completion of construction from Qualified Building Environment Auditors every five years to the Environment Cell with special focus on the following parameters:-

- (a) Energy Use (including all energy sources).
- (b) Energy generated on site from onsite Renewable energy sources.
- (c) Water use and waste water generated, treated and reused on site.
- (d) Waste Segregated and Treated on site.
- (e) Tree plantation and maintenance.

After completion of the project, the Cell shall randomly check the projects compliance status including the five years audit report. The State Governments may enact the suitable law for imposing penalties for non-compliances of the

environmental conditions and parameters. The Cell shall recommend financial penalty, as applicable under relevant State laws for non-compliance of conditions or parameters to the local authority. On the basis of the recommendation of the Cell, the local authority may impose the penalty under relevant State laws. The cases of false declaration or certification shall be reported to the accreditation body and to the local body for blacklisting of Qualified Building Environment Auditors and financial penalty on the owner and Qualified Building Environment Auditors.

No Consent to Establish and Operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 will be required from the State Pollution Control Boards for residential buildings up to 1,50,000 square meters.”;

(II) In the Schedule, for item 8 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“8		Building / Construction projects / Area Development projects and Townships		
8 (a)	Building and Construction projects		≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area	<p>The term “built up area” for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects.</p> <p>Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, but such buildings shall ensure sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV.</p> <p>Note 2.-General Condition shall not apply.</p> <p>Note 3.-The exemptions granted at Note 1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.</p>
8 (b)	Townships and Area Development projects	≥ 3,00,000 sq. mtrs of built up area or Covering an area ≥ 150 ha	≥1,50,000 sq. mtrs and < 3,00,000 sq. mtrs built up area or covering an area ≥ 50 ha and < 150 ha	Note.- General Condition shall not apply”.

[F. No. 19-2/2013-IA-III (Pt.)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide numbers S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009, S.O.695(E), dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E), dated the 13th December, 2012, S.O.674(E), dated the 13th March, 2013, S.O.2559(E), dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014, S.O.637(E), dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E), dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E), dated 7th October, 2014, S.O. 2600(E) dated 9th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E), dated 3rd February, 2015, and S.O. 811(E), dated 23rd March, 2015, S.O. 996 (E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142 (E) dated 17th April, 2015, S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015, S.O. 1834(E) dated 6th July, 2015 and S.O. 2572(E) dated 14th September, 2015, S.O. 141(E) dated 15th January, 2016, S.O. 190(E) dated 20th January, 2016, S.O. 648(E) dated 3rd March, 2016 and S.O. 2269(E) dated 1st July, 2016.

APPENDIX –XIV

ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS

(CATEGORY '1': 5,000 to less than 20,000 Square meters)

MEDIUM	S.N.	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Topography and Natural Drainage	1	The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site. No construction is allowed on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
Water Conservation, Rain Water Harvesting, and Ground Water Recharge	2	<p>Use of water efficient appliances shall be promoted. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed.</p> <p>If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Bye-Laws, 2016.</p> <p>A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area) is recommended. Storage and reuse of the rain water harvested should be promoted. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.</p> <p>All recharge should be limited to shallow aquifer.</p>
	2(a)	At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
Waste Management	3	<p>Solid waste: Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste.</p> <p>Sewage: In areas where there is no municipal sewage network, onsite treatment systems should be installed. Natural treatment systems which integrate with the landscape shall be promoted. As far as possible treated effluent should be reused. The excess treated effluent shall be discharged following the CPCB norms.</p> <p>Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.</p> <p>The provisions of the Solid Waste (Management) Rules 2016 and the e-waste (Management) Rules 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules 2016 shall be followed.</p>
Energy	4	<p>Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.</p> <p>Outdoor and common area lighting shall be Light Emitting Diode (LED).</p> <p>Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level/ local building bye-laws requirement, whichever is higher.</p> <p>Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.</p> <p>Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design.</p> <p>Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.</p>

Air Quality and Noise	5	<p>Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.</p> <p>Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.</p> <p>Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.</p> <p>All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules 2016. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.</p> <p>For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India shall be made.</p>
	5 (a)	The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the CPCB norms.
Green Cover	6	A minimum of 1 tree for every 80 square meters of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
	6 (a)	Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained.

(Category '2': 20,000 to less than 50,000 Square meters)

MEDIUM	S.N.	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Topography and Natural Drainage	1	<p>The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site. No construction is allowed on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.</p> <p>Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.</p>
Water Conservation, Rain Water Harvesting, and Ground Water Recharge	2	<p>A complete plan for rain water harvesting, water efficiency and conservation should be prepared.</p> <p>Use of water efficient appliances should be promoted with low flow fixtures or sensors.</p> <p>The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Bye-laws, 2016.</p> <p>A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.</p> <p>All recharge should be limited to shallow aquifer</p>
	2(a)	At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.

Waste Management	3	<p>Solid waste: Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste.</p> <p>Sewage: Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per CPCB norms. Natural treatment systems shall be promoted.</p> <p>Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.</p> <p>The provisions of the Solid Waste (Management) Rules 2016 and the e-waste (Management) Rules 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules 2016 shall be followed.</p>
	3 (a)	All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
	3(b)	Organic waste compost/ Vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.
Energy	4	<p>Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.</p> <p>Outdoor and common area lighting shall be LED.</p> <p>Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design.</p> <p>Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.</p>
	4 (a)	Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level/ local building bye-laws requirement, whichever is higher.
	4 (b)	Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.
	4 (c)	<p>Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction material quantity. These include flyash bricks, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum blocks, Compressed earth blocks, and other environment friendly materials.</p> <p>Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of the Fly Ash Notification of September, 1999 as amended from time to time.</p>
Air Quality and Noise	5	<p>Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.</p> <p>Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.</p> <p>Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.</p> <p>All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules 2016.</p> <p>All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with</p>

		dust pollution shall be provided with dust mask. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
	5 (a)	The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the CPCB norms.
Green Cover	6	A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
	6 (a)	Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained.
Top Soil preservation and reuse	7	Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.
Transport	8	A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria. <ol style="list-style-type: none"> 1. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic. 2. Traffic calming measures. 3. Proper design of entry and exit points. 4. Parking norms as per local regulation.

(Category '3': 50000 to 150000 m²)

MEDIUM	S.N.	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Topography and Natural Drainage	1	The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site. No construction is allowed on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
Water conservation - Rain Water Harvesting, and Ground Water Recharge	2	A complete plan for rain water harvesting, water efficiency and conservation should be prepared. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provisions are not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Bye-laws, 2016. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. All recharge should be limited to shallow aquifer.
	2(a)	At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
	2 (b)	Use of water efficient appliances should be promoted. Low flow fixtures or sensors be used to promote water conservation.

	2 (c)	Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
Solid Waste Management	3	Solid waste: Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules 2016 and the e-waste (Management) Rules 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules 2016 shall be followed.
	3 (a)	All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
	3(b)	Organic waste composter/Vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.
Sewage Treatment Plant	4	Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per CPCB norms. Natural treatment systems shall be promoted. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.
Energy	5	Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC. Outdoor and common area lighting shall be LED. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
	5 (a)	Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level/ local building bye-laws requirement, whichever is higher.
	5 (b)	Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.
	5 (c)	Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction material quantity. These include flyash bricks, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum blocks, Compressed earth blocks, and other environment friendly materials. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of the Fly Ash Notification of September, 1999 as amended from time to time.
Air Quality and Noise	6	Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site. Wheel washing for the vehicles used be done. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction

		and Demolition Waste Rules 2016. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
	6 (a)	The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the CPCB norms.
Green Cover	7	A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
	7 (a)	Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained.
Top Soil Preservation and Reuse	8	Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.
Transport	9	A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria. <ol style="list-style-type: none"> 1. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic. 2. Traffic calming measures. 3. Proper design of entry and exit points. 4. Parking norms as per local regulation.
Environment Management Plan	10	An environmental management plan (EMP) shall be prepared and implemented to ensure compliance with the environmental conditions specified in item number 1 to 9 above. A dedicated Environment Monitoring Cell with defined functions and responsibility shall be put in place to implement the EMP. The environmental cell shall ensure that the environment infrastructure like Sewage Treatment Plant, Landscaping, Rain Water Harvesting, Energy efficiency and conservation, water efficiency and conservation, solid waste management, renewable energy etc. are kept operational and meet the required standards. The environmental cell shall also keep the record of environment monitoring and those related to the environment infrastructure.

APPENDIX-XV

Accreditation of Environmental Auditors (Qualified Building Auditors)

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), through qualified agencies shall accredit the Qualified Building Environment Auditors (QBEAs). The Qualified Building Environment Auditors could be a firm / organization or an individual expert, who fulfils the requirements. The Ministry will implement this process of accreditation through Quality Council of India (QCI), National Productivity Council or any other organization identified by the Government. The organizations like Indian Green Building Council, Bureau of Energy Efficiency etc. can also be associated in the process of accreditation, training, and renewal. The environmental consultants accredited by the QCI for building sector will be qualified as QBEAs. The QBEAs will meet the following criteria. The accrediting agency can improvise on these criteria.

Qualifications of the Auditor:

- a. Education: Architect (Degree or Diploma), Town Planners (Degree), Civil Engineer / Mechanical Engineer (Degree or Diploma), PG in Environmental Science or any other qualification as per the scheme of the accreditation.

Training:

- b. Mandatory training to be given by the accreditation body or their approved training providers. This will be as per the scheme of the accreditation.

Experience:

- c. At least 3 years of work experience in the related field or building sector Environment Impact Assessment consultants accredited by QCI or any other experience criteria as per the scheme of the accreditation.

Infrastructure and equipment:

- d. As per the scheme of the accreditation

Renewal:

- e. The accreditation will be valid for 5 years and will be renewed as per the process developed under the accreditation scheme.

Accountability/Complaint redressal mechanism: Any complaints regarding the quality of the work of QBEAs shall be made to the accreditation body. The accreditation body shall evaluate the complaint and take appropriate action including black listing or cancellation of the accreditation with wide public notice. This will be in addition to the action at the level of local authority for penalty and blacklisting. The Ministry can also take such action in case of specific complaint or feedback.

APPENDIX-XVI**Environmental Cell at the level of Local Authority:**

An Environmental Cell shall be setup at the local authority level to support compliance and monitoring of environmental conditions in buildings. The Cell shall also provide assistance in environmental planning and capacity building within their jurisdiction. The responsibility of this cell would be monitoring the implementation of this notification and providing an oversight to the Third-Party Auditing process. The cell will operate under the local authority.

Constitution of the cell:

The cell will comprise of at least 3 dedicated experts in following fields:

- a. Waste management (solid and liquid)
- b. Water conservation and management
- c. Resource efficiency including Building materials
- d. Energy Efficiency and renewable energy
- e. Environmental planning including air quality management.
- f. Transport planning and management.

The Cell shall induct at least two outside experts as per the requirements and background of dedicated experts. Existing environmental cells at the level of local authority can be co-opted and trained for this Cell.

Financial Support:

An additional fee may be charged along with processing fee for building permission for integrating environmental conditions and it's monitoring. The local authority can fix and revise this additional fee from time to time. The amount of this fee shall be deposited in a separate bank account, and used for meeting the requirement of salary / emoluments of experts and running the system of online application, verifications and the Environmental Cell.

Functions of the Cell:

1. The cell shall be responsible for assessing and appraising the environmental concerns of the area under their jurisdiction where building activities are proposed. The Cell can evolve and propose additional environmental conditions as per requirements. These conditions may be area specific and shall be notified in advance from time to time. These additional conditions shall be approved following a due consultation process. These environmental conditions will be integrated in building permissions by the sanctioning authority.
2. Develop and maintain an online system for application and payment of fees. The Cell shall maintain an online database of all applications received, projects approved, the compliance audit report, random inspections made. The Cell shall maintain a portal for public disclosure of project details including self certification and compliance audit reports filed by the Qualified Building Environment Auditors for public scrutiny of compliance of environmental conditions by the project.
3. Monitoring the work of Environmental Audit process carried by the Qualified Building Auditors.

4. The Cell shall review the applications; finalize the additional environmental conditions if required within 30 days of the submission of the application to the local authority.
5. The Cell shall adopt risk based random selection of projects for verifying on site for certification of QBA, compliance of environmental conditions and five yearly audit report.
6. The Cell shall recommend to the local authority for financial penalty for non-compliance of environmental conditions by the project proponent.
7. The Cell shall recommend to the accrediting body and the local authority against any Qualified Building Environment Auditor, if any lapse is found in their work.

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH
NEW DELHI**

.....

**ORIGINAL APPLICATION NO. 677 OF 2016
(M.A. NO. 148/2017)**

IN THE MATTER OF:

Society for Protection of Environment
& Biodiversity
Through the Convener
R-7/17, Raj Nagar
Ghaziabad (UP)-201001

.....Applicant

Versus

1. Union of India
Through Secretary, Govt. of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Indira Paryavaran Bhavan, Jorbagh Road,
New Delhi-110003
2. Ministry of Urban Development
Through Secretary, Govt. of India
Maulana Azad Road
Rajpath Area, Central Secretariat
New Delhi
3. Central Pollution Control Board
Through Member Secretary
CBD-Cum-Office Complex
East Arjun Nagar
New Delhi

.....Respondents

AND

**ORIGINAL APPLICATION NO. 01 OF 2017
(M.A. NO. 03/2017 & M.A. NO. 445/2017)**

IN THE MATTER OF:

Pushp Jain
S/o Shri Dhanpat Rai Jain
R/o I A/2C Phase-I
Ashok Vihar
New Delhi-110052

.....Applicant

Versus

1. Union of India
Through the Secretary
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Indira Paryavaran Bhavan
Jorbagh Road,
New Delhi-110003
2. Ministry of Urban Development
Through the Secretary
Maulana Azad Road
Nirman Bhawan
New Delhi 110 011

.....Respondents

AND

**ORIGINAL APPLICATION NO. 7 OF 2017
(M.A. NO. 879/2017)**

IN THE MATTER OF:

Ajay Kumar Singh
236, Lawyers Chambers
M.C. Sitalwad Block
Supreme Court of India
New Delhi

.....Applicant

Versus

1. Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Govt. of India
Through the Secretary
Indira Paryavaran Bhavan
Jorbagh Road,
New Delhi-110003
2. Ministry of Urban Development
Govt. of India
Through the Secretary
Nirman Bhawan
New Delhi 110 011
3. Delhi Development Authority
Through its Vice Chairman
Vikas Sadan, INA
New Delhi
4. Central Pollution Control Board
Through Member Secretary
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar
New Delhi

5. Central Ground Water Authority
Through its Member Secretary
Faridabad
6. Delhi Pollution Control Committee
Through Member Secretary
4th Floor, ISBT Building Kashmeri Gate
New Delhi
7. North Delhi Municipal Corporation
New Delhi
8. South Delhi Municipal Corporation
New Delhi
9. East Delhi Municipal Corporation
New Delhi
10. State Level Environment Impact Assessment
Authority, Delhi Govt. Secretariat
Delhi

.....Respondents

AND

ORIGINAL APPLICATION NO. 55 OF 2017

IN THE MATTER OF:

Mahendra Pandey
S/o Sh. H.C. Pandey
R/o Flat No. 18, Kanishka Apartment
C&D Block, Shalimar Bagh
Delhi

.....Applicant

Versus

1. Union of India
Through Secretary
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Paryavaran Bhavan, Jorbagh Road,
New Delhi-110003
2. Ministry of Urban Development
Through its Secretary
Maulana Azad Road
Rajpat Area, Central Secretariat
New Delhi

3. Central Pollution Control Board
Through its Member Secretary
CBD cut Office Complex
East Arjun Nagar
New Delhi

.....Respondents

AND

**ORIGINAL APPLICATION NO. 67 OF 2017
(M.A. NO. 620/2017)**

IN THE MATTER OF:

R. Sreedhar
R/o A-1/39, 2nd Floor
Freedom Fighter Colony
IGNOU Road, Gate No. 1
Neb Sarhai, New Delhi

.....Applicant

Versus

Union of India
Through the Secretary
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Indira Paryavaran Bhavan
Jorbagh Road,
New Delhi-110003

.....Respondent

COUNSEL FOR APPLICANTS:

Mr. Raj Panjwani, Sr. Advocate
Mr. Ritwick Dutta, Mr. Rahul Choudhary, Ms. Meera Gopal and Mr. Utkarsh Jain, Advocates
Mr. I. K. Kapila & Ms. Disha Singh, Advocates
Mr. Sanjay Upadhyay, Ms. Upama Bhattacharjee and Mr. Salik Shafique, Advocates
Mr. Gaurav Kumar Bansal, Mr. Ompal Shukin and Ms. Nandit Bansal, Advocates

COUNSEL FOR RESPONDENTS:

Mr. B.V. Niren with Mr. Vinayak Gupta, Advocates
Mr. Abhimanyu Garg and Ms. Preety Makkar, Advocates for Government of Puducherry
Mr. Tarunvir Singh Khehar, Ms. Guneet Khehar and Mr. Sandeep Mishra, Advocates and Mr. Dinesh Jindal L.O. for DPCC
Mr. Bairaja Mahapatra, Advocate and Mr. Dinesh Jindal, L.O.
Mr. Rajkumar, Advocate with Mr. Bhupender, LA for Central Pollution Control Board
Mr. D. Rajeshwar Rao, Advocate
Mr. Atma Ram N.S. Naadkarni, Ld. ASG for MoEF&CC
Mr. Divya Prakash Pandey, Advocate

Mr. Utkarsh Sharma, Advocate for State of Uttar Pradesh
Mr. Ravindra Kumar, Advocate for NOIDA Authority
Mr. Krishna Kumar Singh and Mr. Anurag Kumar, Advocates
Mr. Rahul Pratap, Advocate
Ms. Puja Kalra, Advocate

JUDGMENT

PRESENT:

HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR (CHAIRPERSON)

HON'BLE DR. JUSTICE JAWAD RAHIM (JUDICIAL MEMBER)

HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN (EXPERT MEMBER)

Reserved on: 8th November, 2017

Pronounced on: 8th December, 2017

1. Whether the judgment is allowed to be published on the net?
2. Whether the judgment is allowed to be published in the NGT Reporter?

JUSTICE SWATANTER KUMAR (CHAIRPERSON)

By this judgement, we shall dispose of all the five cases connected with Original Application No. 677 of 2016 as a common question of law and fact arises for consideration before the Tribunal in all these cases. However, it is not necessary for us to notice the facts of each case in greater detail and it would be sufficient to refer to the factual matrix of the lead application only, i.e., Original Application No. 677 of 2016, *Society for Protection of Environment & Biodiversity vs. Union of India and ors.*

2. The Applicant-Society claims that it works in the area of environmental conservation and aims at protection of the environment, ecology, natural resources, wildlife and bio-diversity existing on earth. It has filed various cases raising several environmental issues and concerns before the Courts as well as before this Tribunal. According to the Applicant, there is pathetic condition

of urban local bodies in the area under their jurisdiction more particularly in Ghaziabad. The exemption granted from Environmental Clearance for building and construction projects would be a huge retrograde step in the area of environment conservation. It would take us back to a pre- 2004 scenario, i.e., prior to issuance of EIA framework pursuant to specific orders of the Hon'ble Supreme Court. The Applicant believes that such a step will have a disastrous effect on the environment and would cause irreversible damage to the environment. The magnitude of the environmental footprint would be immense and unregulated building and construction activity would cause immense environmental damage. The Ministry of Environment, Forest & Climate Change (for short, "MoEF&CC"), Respondent No. 1 had issued a draft notification dated 29th April, 2016 with regard to amendment of the Notification of 2006 providing exemption to various construction projects all over the country. At that stage, the Applicant had filed an application bearing Original Application No. 168 of 2016 expressing its apprehension and raising serious objections to the draft Notification. The principal contention raised at that time was that the proposed Notification intends to dilute and exempt prior Environmental Clearance for buildings and construction projects through Model Building Bye Laws, 2016, as issued by the Town & Country Planning Organizing, Ministry of Urban Development and the subsequent Notification by Delhi Development Authority of the Unified Building Bye Laws for Delhi, 2016 which were notified vide Notification dated 22nd March, 2016 in pursuance to Chapter-XIV of the Model Building Bye Laws, 2016 and in concurrence with the impugned Notification of MoEF&CC. These amendments and Bye

Laws sought to defeat and do away with the substantive provisions of EIA Notification, 2006 that require prior Environmental Clearance by building and construction projects under item no. 8(a) of the Schedule to EIA Notification, 2006. Original Application No. 168 of 2016 was disposed of by the Tribunal vide its order dated 30th September, 2016 directing MoEF&CC to consider the objections filed by the Applicant prior to issuance of the final Notification. The order dated 30th September, 2016 of the Tribunal reads as under:

“Learned Counsel appearing for the Ministry of Environment, Forests and Climate Change submits that they are in the process of amending the EIA Notification, 2006. According to her the draft Notification has already been published and objections/suggestions have been invited and after expiry of the Statutory period they would issue the final Notification after considering the objections filed.

Learned Counsel appearing for the DDA on instruction from Director of Planning submits that DDA has already notified the unified building bye laws, however, the chapter on environment conditions for sanctioning building plans would not be put into practice/implemented till Ministry of Environment, Forests and Climate Change give its approval/concurrence.

The Learned Counsel appearing for the applicant has raised an issue with regard to the unified bye laws being in conflict with the Notification of EIA, 2006. According to the applicant these objections should be considered.

In view of the statement made by the Learned Counsel appearing for the respective parties, we are of the considered view that nothing survives in this application. The respective authorities will abide by their statements. We also direct the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to consider the objections of the applicant before issuing final Notification so that the unified building bye laws are not in conflict with EIA Notification, 2006.

In view of the above, the Original Application No.168 of 2016 stands disposed of with no order as to cost.”

3. After passing of the above order, Respondent no. 1 issued the final Notification on 9th December, 2016. Though, the objections to the draft Notification was filed by the Applicant on 23rd November, 2016 but no intimation for hearing was given to the Applicant except when the Applicant was invited through Counsel for meeting with Shri Manoj Kumar Singh, Joint Secretary, MoEF&CC, Government of India on 8th December, 2016 to discuss and make presentation on behalf of the Applicant. The discussion went on for about an hour or so and the Applicant was assured that the objections would be considered objectively by the Ministry. However, the final Notification was issued on 9th December, 2016 making substantial changes even in the draft Notification dated 29th April, 2016 which were in total derogation to the environmental laws in force.

4. The Applicant, thus, in the present case prays that the Notification dated 9th December, 2016 should be quashed and set-aside, inter-alia, but primarily on the following grounds:

I. The Impugned Notification not only dilutes but also renders otiose the substantive provisions of Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and even that of Environment (Protection) Act, 1986 (for short, "Act of 1986"). The provisions of the impugned Notification, if implemented would potentially destroy the environment and ecology due to unregulated building and construction activities and will have disastrous effect on environment and would cause irreversible damage to the environment. The magnitude of Environmental footprint would be immense. The objections filed by the Applicant and

others have not been considered objectively and appropriately by the Ministry. The impugned Notification, thus suffers, from the element of non-application of mind as well as is violative of Principle of Natural Justice.

II. The Impugned final Notification is not only at variance with the draft Notification but even introduces new provisions which are diametrically opposite, beyond the scope and purview of the Draft Notification and even had destructive essence to the draft Notification. In this regard, the following significant variance can be noticed:

- (a). Draft Notification did not contain any provision with regard to grant of exemption to the construction building projects from the provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (for short, "Air Act, 1981) and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (for short, "Water Act, 1974) in relation to Consent to Establish and Consent to Operate.
- (b). The composition of the Environmental Cells to monitor the conditions particularly in reference to Environmental Clearance is entirely at variance to the draft Notification.
- (c). Accreditation of Environmental auditors in terms of Appendix XV to the impugned Notification is also at variance from the one proposed in the Draft Notification.

- III. In exercise of subordinate legislative power, a delegatee cannot affect the application of another legislation enacted by the Parliament. In other words, while amending the Notification of 2006 in exercise of subordinate legislation, the delegated authority cannot render the provisions of Water Act, 1974 and Air Act, 1981 as inapplicable and also take away the powers of the Pollution Control Boards under the said Acts, to grant/refuse consent to establish and/or operate to a project.
- IV. Neither any comprehensive study was carried out nor any data collected to support the drastic changes being made by the impugned Notification and also ignored the Precautionary Principle, the fundamental canon of environmental jurisprudence.
- V. The impugned Notification has several deficiencies which are against the basic letter and spirit of the Act of 1986 and the Notification of 2006.
- VI. 'Ease of doing responsible business' cannot be in fact and in law the ground for making amendment to the environmental laws, as it primarily falls beyond the scope of the object and purposes of the environmental laws in force. It is only a ploy to circumvent the provisions of the environmental assessment. The comprehensive process for evaluating the impact on environment due to various projects has been negated by the said amendment.
- VII. Under the impugned Notification, local authority is responsible for development and passing the development

plan vested through the environment cell with the power to impose conditions relating to environmental protection and ensure their compliance. The local authorities which are the sanctioning authorities would also become adjudicatory authorities under the impugned Notification. This dual functioning by the same authority make them judge in their own cause in contravention with the Principle of Natural Justice, *nemo judex in sua causa*, as well as give rise to the plea of conflicting interest.

VIII. Exemption granted under the amended Notification has no nexus to the object sought to be achieved, i.e., the environmental protection.

IX. The impugned Notification is in derogation of India's international commitment and obligation under the Rio Declaration (1992), particularly Principle 15 to 17 and the Paris Agreement, 2015.

X. The impugned Notification, if given effect to, as framed would result in wiping out the effect of environmental laws in force and hence would not be in consonance with the doctrine of non-regression.

XI. In addition to above, Applicant has also contended that the impugned Notification has an impact of disturbing the federal structure as provided in the Constitution of India. The Central Government cannot exercise power, authority and control in relation to subject matter of the Notification over the local authorities. The Environmental Cell, constituted under the amended Notification, would be under control of the local

authority or the State Government, as the case may be and, therefore, it will have apparent conflict with the Central Regulating Authority.

XII. In terms of the Notification, the violations of environmental conditions would be punishable and action would be taken under local laws, thus, divesting the CPCB or the State Regulatory Authority from taking punitive action against the defaulters and, therefore, would not be in consonance with the scheme of 1986 Act. The Notification is a manifest ploy for ousting of the application of the Environmental Acts and even the jurisdiction of the Tribunal. Furthermore, power under Section 3(1) of the Act of 1986 can be exercised in harmony and consonance with other provisions of the Act. The power under Section 3 is to be exercised for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environmental pollution. The measures contemplated under Section 3 can only be taken in that behalf. Thus, power cannot be exercised for purposes beyond Section 3(1) and the provisions of the Act of 1986.

XIII. It is also contended by Applicant that MoEF has not provided any appropriate answer to the questions formulated by the Tribunal in its order dated 21st December, 2016 and 28th July, 2017.

XIV. There is no power with the Central Government to transfer its responsibility to the local authorities. The impugned

Notification does not provide power of refusal or rejection of the application seeking Environmental Clearance. The impugned Notification which introduces Paragraph no. 14 to the Notification of 2006, would be in apparent conflict with Para 1 to 13 of the Notification 2006. The Environmental Cell would not be able to function independently, fairly and in a transparent manner.

XV. The impugned Notification is unsustainable as on one hand it is not based on any study and on the other it ignores the recommendations made in the various studies conducted by the Ministry itself including Dr. Kasturirangan's reports. The positive suggestions and recommendations made in these reports have been ignored. The Notification attempts to hide behind the poor for the benefit of the builders. It also lacks in providing for requisite expertise of the members constituting the environmental cell in the interest of environment. No, criteria or qualifications have been fixed for the Member of environmental cell unlike the law in existence, which certainly would have adverse impacts as there will be massive construction activity causing serious environmental degradation.

5. From the above grounds, the applicants in all these applications pray that the impugned Notification dated 9th December, 2016 should be declared as *ultra vires* and be quashed. The challenge to the Notification is on legal grounds as well as on other reasons that it will have an adverse impact on environment, ecology and natural resources. In fact, it is contended that it will also have serious

repercussion on climate change. The Notification though claims to serve social cause of providing housing for the poor but, in fact, result of its enforcement would be contrary. It would permit construction of huge buildings and apartments without strictly complying with the environmental norms.

6. It will be appropriate to commonly state the response of various respondents together to the applications filed by the applicants. The preliminary objection has been raised as to the maintainability of the applications. It is contended that the validity of the Notification dated 9th December, 2016, has been challenged which is amending the EIA Notification, 2006 in exercise of the power conferred under Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (for short, the 'act of 1986') on the ground that it is violative of Articles 21 and 14 of the Constitution of India, which is beyond the ambit of Section 14 read with Section 18 of the NGT Act and the Tribunal has no jurisdiction to examine the validity of the subordinate legislations. The object of Notification is to delegate the power to Urban Local Bodies to grant Environmental Clearance. The scope of the Environmental Clearance has been widened as, now, Environmental Clearance is required even for building size having a built-up area 5000 sq. mtr. to 20,000 sq. mtr. While under the earlier Notification the built-up area of 20,000 sq. mtr. and above was covered. Urban Local Bodies and Urban Development Authorities are involved in the building plan approval and while granting approval, the process of granting Environmental Clearance can very well be integrated and can be given online. This will hasten the grant of clearances and there would not be any adverse impact on the construction projects. The Notification attempts to

decentralize the clearance process and has also attempted to integrate the environmental conditions along with building permissions. The local authorities would be conferred with the responsibility with support from expert bodies to discharge the important function. It is proposed to have a system of Qualified Building Environment Auditors (QBEA) providing for Third Party Auditing of environmental plans and its implementation. The QBEA will undertake certification that whether the environmental conditions have been adequately planned in the building design or not, it will thoroughly check its implementation during construction and regularly monitor its performance every five years. The setting up of an Environmental Cell at the level of Local Authority has been directed after taking into consideration lack of capacity at the level of Local Authorities. The Environmental Cell will comprise of three dedicated experts in the field of Waste Management (Solid and Liquid), Water Conservation and Management, Resource Efficiency including Building Materials, Energy Efficiency and Renewal Energy, Environmental Planning including Air Quality Management, Transport Planning and Management. The environment cell will also perform various other functions. The Local Authorities will prescribe the fee for environmental appraisal along with the fee for building permissions. Relying upon the judgement of the High Court of Delhi in the case of *Delhi Pollution Control Committee vs. Splendor Landbase Ltd.* in LPA 1/2011 and C.M. No. 6781/2011, the Notification has been issued to grant exemption to the residential complexes from the operation of Air and Water Act, respectively. The High Court expressed the view that residential complexes do not require any permission to establish or

operate under the said Acts. The QBEA is to be accredited by the MoEF&CC through qualified agency which would assess and certify building projects. The project proponent shall submit performance data and certificate of continued compliance of the project for the environmental conditions and parameters applicable after completion of construction from QBEA every five years to the environment cell focusing on different issues. If, there were violations committed by the builders who failed to take prior Environment Clearance in terms of the EIA Notification, 2006 and to deal with the violation in excess, the Ministry had issued certain Office Memorandums granting one time exemption which came to be set aside by the Tribunal *vide* its judgement dated 7th July, 2015 in the case of *S.P. Muthuraman v. Union of India and Ors.* (2015) ALL(I) NGT REPORTER (2) (DELHI) 170. 400 cases were kept on hold at different stages and in order to deal with the same, the present Notification had been issued. The purpose is to bring the entities under Environmental Compliance Regime at the earliest. The Notification provides various stages to be followed for granting prior Environmental Clearance which protects the environment in all respects. The Notification dated 9th December, 2016, provides that the States adopting the environmental conditions prescribed in appendix XIV of the Notification and incorporating it in the building bye laws and relevant state laws and incorporating the said conditions in the approvals given for building construction and making it legally enforceable, shall not require a separate Environmental Clearance from the MoEF&CC. The proposed changes by the State Government in its bylaws are to be examined by MoEF&CC and only after the concurrence of MoEF&CC to the changes

made by the State Government, that the requirement of separate environmental Clearance by the Central government for buildings to be constructed in the State or Local Authority areas, is dispensed with. Appendix XVI provides setting up of Environmental Cell in terms thereof the cell shall be responsible for assessing and appraising the environmental concerns for the area under its jurisdiction where building activities are proposed. The environmental cell can evolve and propose additional environmental conditions as per requirement. The procedure for seeking building permission incorporating environmental conditions has been made more stringent in comparison to the earlier provisions. The burden lies on the project proponent for furnishing requisite information and the Local Authorities are expected to take greater caution and care in assessing them. The comparative analysis of the Notification dated 14th September, 2006 and 9th December, 2016 shows that the later is more comprehensive in terms of prescription of environmental protection standards and conditions. The Notification dated 9th December, 2016 was issued in view of the policy decision taken by the Government of India to provide affordable housing to weaker sections in Urban areas in terms of scheme of 'Housing for All by 2022'. The general conditions that were provided under the Notification of 14th September, 2006 in substance continue but only change that has been brought about is that instead of obtaining prior Environmental Clearance from the Central Government the same shall be obtained from the State/Union Territory Environmental Impact Assessment Authority. The requirement of obtaining prior Environmental Clearance has not been dispensed with. The Draft Notification was

also challenged by the applicant which was disposed of *vide* order dated 30th September, 2016. The suggestions and objections were invited and after considering the same the final Notification was issued. The reliance placed by the applicants on the judgement of *Dr. Avinash Ramkrishna Kashiwar vs. State of Maharashtra*; (2015) 5 Mh. L.J. is of no consequence as on facts that judgement has no applicability in relation to the examination of the present Notification.

JURISDICTION OF THE TRIBUNAL:

7. According to the respondents, reliance placed by the applicant on the judgement in the case of *Dr. Avinash Ramkrishna Kashiwar vs. State of Maharashtra* (supra) is misplaced as that judgement has no application to the facts of the present case and particularly, for examining the validity of the impugned Notification. The respondents, therefore, prayed that the application requires to be dismissed on merits as well as on the preliminary objections taken by them.

8. In light of the above factual matrix of the case, we have to examine the merit or otherwise of the preliminary objections taken by the respondents in regard to the jurisdiction of this Tribunal to examine the validity of the impugned Notification. To examine this issue, we do not have to refer to the facts in any detail suffices it to notice that challenge in the present case is to the legality and validity of the Notification dated 9th December, 2016. The contentions of the respondents are that this Tribunal has been constituted under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010 (for short, Act of 2010) and it being a statutory Tribunal is not vested with the powers to examine the validity or constitutionality of a subordinate

legislation, i.e., Notification dated 9th December, 2016. Such aspects can only be examined by a constitutional Court, i.e., the Hon'ble Supreme Court of India or Hon'ble High Court. Reliance in this regard has been placed by them upon the judgement of the Division Bench of the Bombay High Court in the case of *Central India Ayush Drugs Manufacturers Association, Nagpur & Ors. v. State of Maharashtra*, AIR 2016 BOM 261. The respondents also relied upon the judgement of Hon'ble Supreme Court of India in the case of *Alpha Chem & Anr. v. State of Uttar Pradesh & Ors.*, 1991 Supp (1) SCC 518, wherein it was held that challenge to the constitutionality of a statute is maintainable in proceedings initiated under Articles 226 and 32 of the Constitution of India and not in appeal or revision before High Court or in proceedings initiated under a statute before an authority constituted under the said statute itself. Contrary to this, the contention of the applicant is that the Tribunal is competent and is vested with the jurisdiction and power of judicial review. In exercise of such powers it can examine the constitutionality, validity and legality of a subordinate legislation, particularly, when the Notification issued in exercise of the subordinate legislation is for the implementation of the enactments specified in Schedule I of the Act of 2010. Under the provision of the Act of 2010, such power of the Tribunal is neither expressly nor impliedly barred. On the contrary, the scheme of the Act clearly demonstrates that the Tribunal is competent to examine the correctness of a Notification issued under any of the Scheduled Acts in so far as the Notification implement or impliedly implement the provisions, object and purpose of the scheduled Act under which it is issued. In support of their contention, the applicants rely upon

the judgements of the Hon'ble Supreme Court of India in the case of *L. Chandra Kumar v. Union of India & Ors.*, 1997 (2) SCR 1186, *SP Sampath Kumar v. Union of India & Ors.*, (1987) 1 SCC 124, *State of West Bengal v. Ashish Kumar Roy & Ors.*, (2005) 10 SCC 110 and judgements of this Tribunal in the case of *Wilfred J. v. Union of India* 204 ALL (I) NGT REPORTER 2013, *SP Muthuraman v. Union of India*, 2015 ALL (I) NGT REPORTER (2) DELHI 170 and *Himmat Singh Shekhawat v. State of Rajasthan & Ors.*, ALL (I) NGT REPORTER (1) DELHI 44.

9. As far as this bench of the Tribunal is concerned the question of jurisdiction is no longer *res integra*. It has been conclusively decided by larger bench of the Tribunal in the case of *Wilfred J.* (supra), where the Tribunal held as under:

“39. Having dealt with the constitution of the Tribunal and having established its independence, now let us proceed to examine the scope of power of the Tribunal, with particular reference to examining a subordinate or delegated legislation as being ultra vires, unconstitutional or illegal. Judicial review is the power of the court to review statutes or administrative acts or determine their constitutionality or validity according to a written constitution. In a wider sense, judicial review is not only concerned with the merits of the decision but also the decision making process. It tends to protect individuals against the misuse or abuse of power by a wide range of authorities. Judicial review is a protection to the individual and not a weapon. It is the doctrine under which legislative and/or executive actions are subject to review (and possible invalidation) by the judiciary. A specific court with the power of judicial review may annul the acts of the State, when it finds them incompatible with a higher authority (such as the terms of a written constitution). Judicial review is an example of checks and balances in a modern governmental system, where the judiciary checks the other branches of government. This principle is interpreted differently in different jurisdictions, which also have differing views on the different hierarchy of

governmental norms. As a result, the procedure and scope of judicial review may differ from country to country and State to State. Unlike in England, where the judiciary has no power to review the statutes/Acts made by the Parliament, the United States Supreme Court in terms of Article III and Article VI exercises the power of judicial review of the Acts passed by the Congress and has struck down several statutes as unconstitutional. In India, the Supreme Court and the High Courts have frequently exercised the power of judicial review keeping intact the 'doctrine of separation of power'. Challenge to legislation before the Courts in India has primarily been permitted on a very limited ground. The legislation in question should either be unconstitutional, or should lack legislative competence. Challenge to such legislation as being unreasonable has also been permitted, if it violates or unreasonably restricts the fundamental rights, particularly under Article 14 and 19 adumbrated in our Constitution.

40. The Courts are vested with the power of judicial review in relation to legislative acts and even in relation to judgments of the Courts. The power of judicial review has been exercised by the Courts in India sparingly and within the prescribed constitutional limitations. The Courts have also taken a view that functions of the Tribunal being judicial in nature, the public have a major stake in its functioning, for effective and orderly administration of justice. A Tribunal should have judicial autonomy and its administration relating to dispensation of justice should be free of opinions. (*Ajay Gandhi v. B. Singh*, (2004) 2 SCC 120). The National Green Tribunal has complete control over its functioning and all the administrative powers, including transfer of cases, constitution of benches and other administrative control over the functioning of the Tribunal, are vested in the Chairperson of the NGT under the provisions of the NGT Act”.

10. The Tribunal in the case of *S.P. Muthuraman* (supra) also held that:

“This Tribunal has been vested with Original, Appellate and Special jurisdiction in regard to directing payment of compensation for damage to and for restitution and restoration of the environment. The legislature in its wisdom worded the provisions relating to the jurisdiction of the Tribunal (Sections 14 to 17 of the Act

of 2010) very widely, and with a clear intent to provide this Tribunal with jurisdiction of a very wide magnitude. Upon reading the various provisions of the Act of 112 2010 cumulatively and in light of the underlying scheme of the Act of 2010, including the definition of 'environment' in terms of Section 2(c) of the Act of 2010, it is quite clear that this Tribunal is having all the trappings of a Court and is conferred with the twin powers of judicial as well as merit review. There is no provision in the Act of 2010 which curtails the jurisdiction of the Tribunal to examine the validity and correctness of a delegated legislation and/or administrative or executive order passed by the Government including any of its instrumentalities or authorities. The fundamental principle for invoking the jurisdiction of this Tribunal is that, the question raised should be a substantial question relating to environment and should arise out of the implementation of the enactments specified in Schedule I of the Act of 2010. It could even relate to enforcement of any legal right relating to environment with regard to these enactments. Delegated or subordinate legislation, executive orders and/or administrative orders in so far as they relate to the implementation of the Scheduled Acts would be open to challenge before the Tribunal and hardly any argument can be raised that the documents like Office Memoranda would not be subject to judicial scrutiny before the Tribunal".

11. The parties to the *lis* had preferred statutory appeal against the above cited judgement of the Tribunal before the Hon'ble Supreme Court of India. The Hon'ble Supreme Court of India had issued notice on the appeals and *vide* its order dated 21st January, 2015 in Civil Appeal No. 7884-7885 of 2014 had directed that further proceedings qua the appellants shall remain stay till further orders. However, in the same order the Hon'ble Supreme Court also directed that this Tribunal shall continue to exercise its powers in terms of Section 14, 16 and 18 of the NGT Act, 2010 in other cases. *Vide* order dated 3rd

February, 2016, passed by the Hon'ble Supreme Court of India in another set of appeals being Appeals No. 8550-8551 of 2014 passed an order by modifying order dated 21st January, 2015. The order dated 3rd February, 2016 reads as under:

“.....By our Order dated 21.01.2015, we had stayed further proceedings in Appeals No. 14 of 2014, 17 of 2014 and 88 of 2014 and Original Application No. 74 of 2014 pending before the National Green Tribunal, Principal Bench at Delhi. Having heard learned counsel for the parties at some length, we are inclined to modify the said order so as to permit the Tribunal to proceed with the hearing of the Appeals and the Original Application for an expeditious disposal of the same. Learned counsel for the parties also agree that the appeals and the original application could be finally heard and that neither party shall pray for any interim direction in the said matters nor seek any adjournment which may unnecessarily procrastinate the entire controversy.

In the circumstances, therefore, we modify our Order dated 21.01.2015 and permit the National Green Tribunal, Principal Bench at Delhi to proceed with the hearing of the appeals and Original Application and make an endeavour to dispose of the same as far as possible within a period of six weeks from the date a copy of this 3 order is placed before it. We make it clear that hearing of the Appeals and O.A. on merits pending before the Tribunal shall be without prejudice to the contentions open to the parties in these appeals which shall await the final hearing and disposal of the matter by the Tribunal. These appeals shall accordingly stand over for being listed after the disposal of the matters by the Tribunal. Liberty is given to the parties to mention the matter once the Tribunal passes final orders in the case before it.”

In terms of the above order, the matters were finally heard by the Tribunal and disposed of *vide* order dated 2nd September, 2016. The parties had approached the Hon'ble Supreme Court after the final judgement by the Tribunal. The matter was heard by the Hon'ble Supreme Court and the Appeals were disposed of *vide* order dated 3rd

July, 2017. The order dated 3rd July, 2017 while leaving the question of law open, reads as under:

“.....Pursuant to the order dated 3rd February, 2016, the National Green Tribunal has delivered judgment and order dated 2nd September, 2016. A review petition filed against that decision was disposed of on 30th November, 2016.

We are told by the learned Attorney General that the project has been upheld by the National Green Tribunal. Under the circumstances, we dispose of these appeals leaving open the question decided by the National Green Tribunal on its jurisdiction to set aside subordinate legislation.

In the event any of the aggrieved parties raises a dispute against the final order passed by the National Green Tribunal, it will be open to the appellant as well as the State of Kerala to agitate the issue of a 2 challenge to the subordinate legislation.

Pending applications, if any, are disposed of.”

In terms of the above order, it is clear that the law stated by the Tribunal in its judgement in the case of *Wilfred J. (supra)* was not disturbed by the Hon’ble Supreme Court either at the interim stage or while finally disposing of the appeals. Interim stay granted by the Hon’ble Supreme Court was limited to the appeals with a specific dictum that the Tribunal could decide other cases in terms of the provisions of the Act thereby clearly stating that the judgement in the case of *Wilfred J. (supra)* on the question of law was neither interfered nor stayed. Thus the law stated by the larger bench of the Tribunal attains finality and is binding on this bench. In any case, we have no reason not to accept the mandate of the larger bench and apply to the present case. The reliance placed by the respondents upon the judgement of the High Court of Bombay in the case of *Central India Ayush (supra)* will not be of any benefit to the respondents. Firstly,

the judgement of the High Court of Bombay does not consider the larger bench of the Tribunal in the case of *Wilfred J.* (supra). It also does not refer to the judgements of the Hon'ble Supreme Court in *L. Chandra Kumar* (supra) wherein Hon'ble Supreme Court had clearly stated that the Tribunals are competent to hear matters challenging *vires* of the statutory provisions or *vires* of the subordinate legislation. Of course such jurisdiction falls in a limited compass. In the case of *SP Sampat Kumar* (supra), the Hon'ble Supreme Court clearly stated that the Tribunal has power of the judicial review and even vested with the powers of the Civil Courts so it has wide jurisdiction including the power of judicial review. There are other judgements from other High Courts which have taken entirely a different view than the view taken by the High Court of Bombay. These High Courts have specifically referred to the Tribunal for adjudication of cases involving challenge to the Notifications issued in exercise of subordinate legislation with regard to noise pollution, plastic bags and other such matters. In this regard, we may refer to the judgement of the High Court of Delhi in the case of *All India Plastic Industries Association & Anr. v. Govt. of NCT of Delhi and Ors*, Writ Petition No. 7012 of 2012 decided on 5th December, 2016. The Division Bench of the High Court while relying upon the judgement of *L Chandra Kumar* (supra) of the Hon'ble Supreme Court of India and the provisions of the Schedule I to the Act of 2010, held that the matter before it challenging the Notification issued under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (for short, 'act of 1986') imposing a ban on manufacture, import, store, sale or transport of any kind of plastic, carrying bags etc be transferred to this Tribunal for deciding

the same on merits including the question, validity of the Notification. It may be noticed that High Court of Delhi would be the jurisdictional High Court for the Principal Bench, National Green Tribunal.

12. The Punjab & Haryana High Court, Tripura High Court and Jharkhand High Court has also transferred the cases of *Goodwill Plastic Industries & Ors. v. Union Territory of Chandigarh & Ors.*, *All India Plastic Industries Association v. Tripura* and *RDS Bricks v. State of Jharkhand*, respectively to the Tribunal. In all these cases, *vires* to the Notifications dated 30th July, 2008 and 3rd July, 2013 both relating to banning of plastic and Notification dated 29th March, 2012 relating to eco-sensitive zone were challenged. To put it simply all these High Courts have taken a view that the Tribunal can examine the validity of a Notification issued for implementation of a subordinate legislation.

In the another judgment of the Tribunal in the case of *SP Muthuraman v. Union of India & Anr.* (supra), wherein the office memorandums issued by the MoEF&CC dated 12th December, 2012 and 27th June, 2013 were quashed. The Tribunal took the view that it had the limited power of judicial review and it can examine the office memorandums issued in furtherance to the rules framed by MoEF&CC. A review application was filed by the different project proponents in that case, which was also dismissed *vide* order dated 1st September, 2015. The orders of the Tribunal were challenged before the Hon'ble Supreme Court of India and the Hon'ble Supreme Court *vide* its order dated 24th September, 2015, stayed the order of the Tribunal. *Vide* order dated 23rd November, 2015 and upon application

of MoEF&CC the Hon'ble Supreme Court of India clarified its order and stated that stay was applicable only to the appellant's before it. During the pendency of the appeals, some directions were passed by the Hon'ble Supreme court in relation to deposit of the environmental compensation imposed by the Tribunal. The Hon'ble Supreme Court *vide* order dated 4th July, 2016 made it clear that the Tribunal could proceed by passing of directions as contained in para 163(13) of its order dated 7th July, 2015 and parties were granted liberty to raise all submissions open to them on fact and law before the Tribunal. Even the judgement of the Tribunal on the question of jurisdiction has not been stayed by the Hon'ble Supreme Court. However, the parties have been granted liberty to raise all pleas of facts and law. The Tribunal had also passed similar judgments in the case of *Himmat Singh Shekhawat v. State of Rajasthan* (supra) and *Kalpvrksha & Ors. v. Union of India*, in OA No. 116 of 2013 (T_{HC}) decided on 17th July, 2014. All these orders have attained finality and remain undisturbed.

13. Another aspect that needs specific mentioning by us is that this Tribunal is a special and unique Tribunal constituted under the legislation enacted by the Parliament in exercise of its powers under Article 253 of the Constitution of India. It needs to be distinguished from other Tribunals enacted under Article 323(A) and 323(B) of the Constitution. This Tribunal has been constituted for the purpose of implementing the decisions at the United Nations Conference on the Human Environment held at Stockholm in June 1972, where India also participated. 186th Law Commission Report also noticed that the environmental Tribunal constituted under Article 253 could be traced

as an act of implementation of the decisions taken at the International Conference with reference to Rio-declaration of 1992. The purpose of implementing the decisions at Rio conference & Stockholm Conference and constituting the Tribunal was to provide speedy adjudicatory body in respect of the disputes arising in environmental matters. In the case of *Braj Foundation vs. State Government of UP & Ors.*, Application No. 278 of 2013 decided on 5th August, 2014, the bench of the Tribunal held that one is to remember that the Tribunal is created in furtherance to the enactment of the Parliament to give effect to the true spirit of the terms of Article 253 of the Constitution of India and, therefore, there is no iota of doubt in our mind that the Tribunal has inherent power of not only enforcing its orders but also dealing with any person who either disobeys or violates its orders. The inherent power would co-exist with the Tribunal examining the correctness of any office order or subordinate legislation whether it is in consonance or not with the provisions of the environmental laws in force particularly when it is issued under those very legislations.

In light of the above position of law and the fact that the judgments of the Tribunal in the case of *Wilfred J.* (supra) and *S.P. Muthuraman* (supra) are binding upon this bench. We have no hesitation in rejecting the objection raised by the respondents as without merit.

DISCUSISON ON MERITS OF THE CONTENTIONS RELATING TO VALIDITY OF THE NOTIFICATION

14. The draft Notification dated 29th April, 2016 was published by the Respondent inviting objections and suggestions thereto. After

considering the objections/suggestions received by the MoEF&CC, it had issued the final Notification dated 9th December, 2016. According to the Applicant, not only the Notification dated 9th December, 2016 but also the entire process of finalizing the Notification suffers from factual and legal infirmities. It is also the contention that it defeats the very object and purpose of the Act of 1986, EIA Notification of 2006 and is also opposed to the federal scheme under the Constitution of India. The detailed objections raised by the Applicant has already been noticed by us in paragraph no. 4 of the judgment (supra). According to the respondent, the notification does not suffer from any error much less legal infirmity or validity. The contentions of the respondents have also been noticed above. And within the ambit of the contentions raised before us, now, we will proceed to deliberate on these issues. First and foremost, we may refer to the comparative study of the existing and proposed regime in terms of the Notifications dated 14th September, 2006 and 9th December, 2016. The useful reference can be made to the following chart:

Sl. No.	Particulars	EIA Notification dated 14 September, 2006	EIA Notification dated 09 December, 2016
1.	Consent to Establish & Operate	<ul style="list-style-type: none"> • Prior to the actual construction activities, the project proponent has to obtain Consent to Establish from the Board under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for all construction projects having BUA above 20,000 m² • After completion of the construction activity, the proponent has to obtain Consent to Operate from the Board under the Water 	<ul style="list-style-type: none"> • No Consent to Establish and Operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 will be required from the State Pollution Control Boards for residential buildings up to 1,50,000 square meters

		(Prevention <input type="checkbox"/> No Consent to Establish and Operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 will be required from the State Pollution Control Boards for residential buildings up to 1,50,000 square meters and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for all construction projects having BUA above 20,000 m ² .	
2.	Construction projects having built up area below 20,000 m ²	<ul style="list-style-type: none">• Projects having built up area below 20,000 m² not require prior environmental clearance from MoEF	<ul style="list-style-type: none">• BUILDINGS CATEGORY '1' (5,000 to < 20,000 Square meters) → A Self declaration Form to comply with the environmental conditions (Appendix XIV- attached below) along with Form 1A and certification by the Qualified Building Environment Auditor to be submitted online by the project proponent besides application for building permission to the local authority along with the specified fee in separate accounts → Thereafter, the local authority shall issue the building permission incorporating the environmental conditions in it and allow the project to start based on the self declaration and certification along with the application → After completion of the construction of the building, the project proponent may update Form 1A online based on audit done by the Qualified Building Environment Auditor and shall furnish the revised compliance undertaking to the local authority. → Any non-compliance issues in buildings less than

			20,000 square meters shall be dealt at the level of local body and the State through existing mechanism
3.	Construction Projects having built up area above 20,000 m ²	<ul style="list-style-type: none"> An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form 1 annexed herewith and –The project proponent to submit online application in Form 1 A along with specified fee for environmental appraisal and additional fee for building permission –The fee for environmental appraisal will be deposited in a separate account Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. 	<ul style="list-style-type: none"> The project proponent to submit online application in Form 1 A along with specified fee for environmental appraisal and additional fee for building permission –the fee for environmental appraisal will be deposited in a separate account. The Environment Cell will process the application and present it in the meeting of the Committee headed by the authority competent to give building permission in that local authority –The Committee will appraise the project and stipulate the environmental conditions to be integrated in the building permission –After recommendations of the Committee, the building permission and environmental clearance will be issued in an integrated format by the local authority –The project proponent to submit Performance Data and Certificate of Continued Compliance of the project for the environmental conditions parameters applicable after completion of construction from Qualified Building Environment Auditors every five years to the Environment Cell with special focus on the following parameters; 1.Energy Use (including all energy sources) 2.Energy generated on site from onsite Renewable energy sources 3.Water use and waste water generated,

			<p>treated and reused on site 4.Waste Segregated and Treated on site 5.Tree plantation and maintenance –After completion of the project, the Cell shall randomly check the projects compliance status including the five years audit report –The State Governments may enact the suitable law for imposing penalties for non-compliances of the environmental conditions and parameters –The Cell shall recommend financial penalty, as applicable under relevant State laws for noncompliance of conditions or parameters to the local authority.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On the basis of the recommendation of the Cell, the local authority may impose the penalty under relevant State laws –The cases of false declaration or certification shall be reported to the accreditation body and to the local body for blacklisting of Qualified Building Environment Auditors and financial penalty on the owner and Qualified Building Environment Auditors
4.	Built up Area considered for EC	<ul style="list-style-type: none"> • Built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area 	<ul style="list-style-type: none"> • The term “built up area” for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects
5.	Monitoring of environmental compliances	<ul style="list-style-type: none"> • Earlier, it was mandatory for the project proponent to submit compliance report every six months. 	<ul style="list-style-type: none"> • Project proponent shall submit performance data & certificate of continued compliance of the project for the environmental conditions after completion of construction every five years.

6.	Process of granting permission for construction and building projects	<ul style="list-style-type: none"> Under 2006 notification prior Environment clearance from SEIAA was mandatorily required even before <u>starting of the construction work or preparation of land</u>. SEIAA was to screen scope and appraise projects before granting of environment clearance. The environmental clearance process before SEIAA comprises of four stages, all of which may not apply to particular cases as set forth. These four stages in sequential order are:- <ul style="list-style-type: none"> Stage (1) Screening (Only for Category 'B' projects and activities) Stage (2) Scoping Stage (3) Public Consultation Stage (4) Appraisal 	<ul style="list-style-type: none"> Under 2016 notification Environmental conditions are to be imposed by Environmental cell at the level of local authority. The cell will then process the application and place it before the committee headed by the authority competent to give building permissions. The committee will then appraise the project and stipulate environmental conditions without any provisions of public consultation which is an integral part of 2006 notification. Therefore, the environmental cells work under the building permit issuing authority therefore not a independent authority to impose environmental conditions. Moreover building permit authority is not a scientifically sound body as SEIAA or SEAC.
7.	Environment Clearance Authority concerning Building and Construction projects	<ul style="list-style-type: none"> Clearance was given after screening and appraising of the projects by government constituted bodies' i.e. SEIAA or SEAC who are independent bodies. 	<ul style="list-style-type: none"> Imposition of environmental conditions by local authority on the basis of assessment and certification by Qualified Building Environment Auditors (QBEAs) which could be a firm /Organization or an individual expert accredited by the accreditation authority.
8.	Violation of environmental conditions	<ul style="list-style-type: none"> Violation of environmental conditions and parameters are dealt under section 15 and section 19 of EPA, Act 1986. 	<ul style="list-style-type: none"> The state Government may enact suitable laws for imposing penalties for non compliance. The local Authorities shall impose penalties based on the recommendation of environmental cell of local body.
9.	Qualification of Experts	<ul style="list-style-type: none"> Multi sectoral / Multi disciplinary experts in SEAC. Qualification as per the Schedule 6 of the 	<ul style="list-style-type: none"> Experts of limited sectors like Water, Air, Solid Waste, Energy and transport in environmental cell.

		current EIA notification.	
--	--	---------------------------	--

From the above comparative study of the two regimes, it is clear that the regime in terms of the Notification dated 9th December, 2016 would considerably dilute the environmental safeguards provided not only under the Regulation of 2006 but even under the Act of 1986. The Applicants have rightly placed reliance on the Principle of Non-regression. Under the International law, the doctrine of Non-regression is an accepted norm. It is founded on the idea that environmental law should not be modified to the detriment of environmental protection. This principle needs to be brought into play because today environmental law is facing a number of threats such as deregulation, a movement to simplify and at the same time diminish, environmental legislation perceived as too complex and an economic climate which favours development at the expense of protection of environment. The draft amendment of the existing environmental laws should be done with least impact on environment protection that was available under the existing law or regime. The present amendment in the Notification particularly few clauses that we will refer hereinafter can lead to severe environmental impacts.

15. The Precautionary Principle as propounded by the Hon'ble Apex Court is a cornerstone of environmental jurisprudence in the country as the environmental conditions imposed are not comprehensive enough and are only a tick-box exercise taken by the project proponent without any prior environment assessment process especially its impact on ecologically sensitive area and other environmental vulnerable area.

The impugned notification, takes away the power of the Pollution Control Boards and Committee to grant/refuse Consent to Establish and Consent to Operate for building and construction projects up to an area of 1,50,000 sq meter. It further dilutes the entire environmental assessment framework under the EIA notification 2006, which has been periodically strengthened and amended by the numerous orders of this Hon'ble Tribunal.

The impugned notification has several deficiencies that go against the basic letter and spirit of EPA Act, 1986 and the EIA notification issued there under. Power under Section 3 read with Rule 5 of Environment (Protection) Act, 1986 can only be exercised by the central government or the authorities constituted by it. Whereas the impugned notification gives power to the State Government for constitution of an authority to exercise and perform such of the powers and functions as provide under Environment Protection Act, 1986, which Includes assessment and granting of environment clearance to the projects. This would be apparently in conflict with the provisions of the Act of 1986. In this regard reference can also be made to the judgement of the constitutional bench of the Hon'ble Supreme Court in the case of *LIC v. Escorts Ltd.*, (1986) 1 SCC 264, where the Hon'ble Supreme Court held that it may be open to a subordinate legislating body to make appropriate rules and regulations to regulate the exercise of a power which the Parliament has vested in it, or as to carry out the purposes of the legislation, but it cannot divest itself of the power.

It is further stated that these conditions fall substantially below the prior environmental assessment procedure which was much detailed and brought within EIA framework after the direction of the Hon'ble Supreme Court in the *Maily Yamuna Case* (W.P.C No. 725 of 1994).

16. The impugned notification provides that the local authorities such as the development authorities and Municipal Corporation may certify compliance of Environmental Conditions prior to issuance of completion certificate based on recommendations of the Environmental Cell to be constituted in the local authority. Further, the purpose of notification regarding integration of environmental conditions, the MoEF&CC through competent agencies would accredit Qualified Building Environmental Auditor (QBEA's) to assess and certify the building projects. It is clear from the above that the entire assessment procedure has been replaced over which the MoEF&CC has no control.

17. The MoEF&CC has failed to produce any study, literature, evaluation of the reason for taking such a retrograde decision to go back to a pre-2004 situation wherein the failure of the local bodies was considered to be the primary reason for bringing building and constructions activity within the EIA framework. In pre-2004 the position was that the construction sector projects were only regulated through Bye Laws and no Environmental Clearance was required.

18. The proposal for exemption of Environmental Clearance for construction and building project with built-up area to 1,50,000 Sq mtrs. is baseless as there is no study that indicates any improvement

in environment quality with regard to all environmental facets/ availability of natural resources, following which there can be a consideration for relaxation of current norms.

The said amendment notification is only a ploy to circumvent the provisions of environmental assessment under the EIA Notification, 2006 in the name of 'ease of doing responsible business' and there is no mechanism laid down under the amendment notification for evaluation, assessment or monitoring of the environment impact of the building and construction activity. The construction industry consumes enormous resources and has a significant energy footprint; the sector emits 22 per cent of India's total annual carbon-dioxide emission. The Hon'ble Tribunal in the matter of *S.P. Muthuraman vs. Union of India & Anr.* (supra) Observed:

"In recent past, building construction activities in our country have been carried out without much attention to environmental issues and this has caused tremendous pressure on various finite natural resources. The green cover, water bodies and ground water resources have been forced to give way to the rapid construction activities. Modern buildings generally have high levels of energy consumption because of requirements of air-conditioning and lighting in addition to water consumption. In this scenario, it is necessary to critically assess the utilization of natural resources in these activities."

19. The very purpose of including the construction projects in the EIA Notification was the failure of the local bodies to ensure compliance with environmental norms. The ULB's/DA's have always had specific stipulation on environmental concerns. However, such conditions were never adhered to or made a pre-requisite to such sanction. It was therefore the case of MoEF&CC that the local body have been approving new construction projects without adhering to

environmental norms. Now, the MoEF&CC itself is taking a step in backward direction without there being any changes brought about in the capacity and technical competence of the local body to assess, evaluate and monitor the environmental norms or to ensure compliance.

20. The EIA Notification, 2006, has a comprehensive process for evaluating the impact on environment which will not be the case after the said notification. For instance, the EIA Notification, 2006 provides Expert Appraisal Committee at the Centre and the State Expert Appraisal Committee at the State level. The composition of these committees comprises as per Appendix-VI to EIA Notification, 2006 of independent experts, such as, Environment Quality Expert, Sectoral Expert in Project Management etc. But as per the amendment notification the same local body which is responsible for the stipulation of the condition would be responsible for ensuring the compliance of the same with the help of Environmental cell and QBEAs. This is in contravention of the principle of *nemo judex in sua causa*, which is a principle of natural justice, meaning that a person cannot be judge of his own cause. Also, there is no technical expertise or competence within the local bodies to either evaluate impact or to ensure compliance of environmental conditions.

As per the EIA Notification 2006, clause 1.3 states “*what are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities)*. But as per the amended notification of 2016, no such provision is laid down.

21. This Hon'ble Tribunal in O.A. No. 171 of 2013 (*NGT Bar Association vs. MoEF*) vide Order dated 13.01.2015 stated "*We direct Secretary, MoEF along with such experts and the States Afore referred will also consider the possibility of constituting the branches of SEIAA at the district or at least, division levels to ensure easy accessibility to encourage the mine holders to take EC*". Similarly, the O.M. dated 19.06.2013 states that "*In case of a large pendency case the concerned state Government feels that there is need for another SEAC, the State Government may accordingly send the proposal to MoEF&CC for setting up/notifying another SEAC and MoEF may consider the same*". However instead of adhering to their own O.M.'s and the categorical judgement of the this Tribunal, they have chosen to completely dilute EC process and violate the EIA Notification, 2006 and thereby Act of 1986.

22. A bare perusal of amendment notification would show that there is complete dilution of the norms as provided under the EIA Notification, 2006. For instance, totality of issues related to conservation of water is completely ignored for building of built-up area up to 5000 sq.mtr. There is no sewage treatment or municipal solid waste processing facilities stipulated within the premises for building up to 5000 sq. mtr. of built up area.

23. The MoEF&CC has failed to fulfil its statutory responsibilities. By transferring the powers to ULBs/ Development Authority, it has created a situation of conflict of interest as all the powers have been vested with the same authority. National documents (CAG Report, 2016) also discourage such an integration of environment condition to

the sanctioning authority under the urban local bodies instead of independent assessment by environmental experts of building and construction projects. Thus for example, the report by Comptroller and Auditor General of India (CAG Report, 2016) clearly states that urban local bodies have not been performing on environmental parameters. In most compliance audit, the environmental parameters including MSW, Waste minimisation, e-waste etc have been grossly violated.

It is submitted that on para wise comparison of the draft notification and final notification are entirely different. The main addition which were not part of draft notification but found place in the final notification are as follows:

- *Consent to establish and Consent to Operate under Water Pollution Act, 1974 and Air Pollution Act, 1981 will not be required from SPCB for residential buildings up to 1,50,000 sq.m.*
- *Stripping of building construction projects of built up area of 20,000 sq.m upto 1,50,000 sq.m. from the purview of EPA Act, 1986 and bringing under the concerned State Laws.*
- *The draft Notification specifically mentions that the exclusion/amendments mentioned in the draft notification are not intended for hospitals whereas the final notification clearly excludes hospitals also from the purview of EIA Notification and EPA Act, 1986.*
- *Addition of Appendix-XV, Accreditation of Environmental Auditors. (qualified Building Auditors).*
- *Addition of Appendix-XVI, Environmental Cell at the level of Local Authority.*

When the residential building construction projects of built up area more than 20,000 sq.m up to 1,50,000 sq.m are excluded from

the requirement of “Consent to Establish” or “Consent to Operate” then these building construction projects will be out of the purview of these statutes, what will be the relevance of CPCB norms and this will encourage indiscriminate discharge of untreated sewage into river and drains.

24. In the said notification, there is no definition of “Area”. In the absence of such a definition, the “Area” can be for the whole of the State or District or Region. In this connection, attention is brought to the EIA Notification, 2006 wherein the word “built-up area” was introduced. There was no definition of “built up area” in the impugned Notification and which leads to confusion in the building construction sector.

The said notification is contrary to the recommendations of the report of the committee constituted by MoEF&CC on 11.12.2012 (The Kasturirangan report) to review the provisions of EIA Notification, 2006 relating to buildings, etc which was then accepted by MoEF&CC. The MoEF&CC vide OM dated 10.11.2015, reiterated and vetted the recommendations of Kasturirangan Committee among other things. If the MoEF&CC is now changing its stand, it is duty bound to produce back-up study or research material to prove that the local bodies have concern towards environment.

25. Besides noticing the above mentioned deficiencies in and dilutions of the existing laws by the impugned Notification, we must also notice a very strong legal infirmity in it. Admittedly, the notification has been issued by the MoEF&CC in exercise of its powers under sub-section (1) read with clause (V) of sub-section (2) of Section

(3) of the Act of 1986 and clause (d) of sub-rule (3) of Rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986. By the impugned Notification, paragraph 14 is sought to be inserted after paragraph 13 of the existing Notification/Regulations of 2006. The powers under these provisions can be exercised under Section 3(2)(5) of the Act of 1986 which empowers the Central Government to take measures to protect and improvement of the quality of environment in regard to restrictions of areas in which any industry/operations or process or class of industries operations or processes shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguards. In terms of section 3 (1) of the Act, this power of taking measures is to be exercised by the Central Government when it deems necessary and expedient for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing, controlling and abating environmental pollution (emphasis supplied). Rule 5 deals with the prohibition and restriction on the locations of industries and the carrying on process and operations in different areas. It gives power to the Central Government to take into consideration the factors while prohibiting or restricting the locations of industries and carrying on of process/operations in different areas. Sub-rule 3 of this Rule contemplates the procedure to be followed by the Central Government while issuing the notification for imposing prohibition or restriction as stated in Sub-rule (1) of Rule 5.

Thus, both the sections and the rule gives power for issuing of any notification and placing prohibition / restriction in their terms, subject to the conditions, i.e., while issuing notification the procedure under Rule 5 (3) should be followed and more importantly it should be

exercised only for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing pollution. Once any of these essential statutory features are missing the notification issued would be liable to be interfered with. The major part of the Notification does not satisfy these ingredients.

26. The amended clause 14 while dealing with the other building category more than 20000 sq. meter also provides that no Consent to Establish and Operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 will be required from the State Pollution Control Boards for residential buildings upto 150000 sq. meter. This amendment is *ex facie* opposed to the above objects and in fact lacks legislative competence. While exercising powers under a subordinate legislation in furtherance to Section 3 and Rule 5, the authority cannot in exercise of its subordinate legislation exclude the operation of a substantive law that is Water Act, 1974 and Air Act, 1981 enacted by the Parliament. This would suffer from the *vires* of excessive legislation. It is strange that the MoEF&CC, a delegatee under the said provision could venture upon excluding the application and enforcing of a Parliament Act without even making any amendment under that act or the rules framed under that act. This action of the MoEF&CC cannot stand the scrutiny of law.

27. The Environmental Cell is to be constituted by the local authority or the State Government, whereas the implementation of the environmental law is vested with the Central Government. The Environmental Clearance is expected to be issued by the authorities

in an integrated format. Any offence or violation thereto which is punishable under the Act of the Parliament, i.e., the Act of 1986 thus subordinate legislative amendment takes away that power and requires a local authority to take precedence in relation to providing punishment for such violation or offence. There is clear ambiguity and uncertainty in the Constitution of the Environmental Cell and its functions. There is no clarity as to the qualification which the Member of the Environmental Cell should possess. A Cell, primary duty of which is to protect the environment would have to work in subordination to a local authority whose primary object is to permit development. Thus, the possibility of conflicting interest arising in the functioning of the local authority and the Environmental Cell cannot be ruled out. It may arise even then thus defeating the very purpose of the amendment.

28. Another serious objection raised to the Notification is that the final Notification has been issued without considering the objections filed to the draft Notification. Of course, in terms of the procedure prescribed under Rule 5(3) of the Rules of 1986 the procedure must be strictly adhered to. The MoEF&CC had invited objections which were filed and even the Applicant was heard. There cannot be a doubt that requirement of considering objections effectively is not a mere formality. It should be done objectively and in accordance with law as held in the case of *Dr. Avinash Ramkrishna Kashiwar vs. the State of Maharashtra (supra)*:

17."It could thus be seen that it appears to be settled position of law that the requirement of previous publication inviting objections and suggestions is not

an empty formality. It is with an intention to enable persons likely to be affected , to be informed, so that they may take steps as may be open to them and the objections/suggestions made would be required to be taken into consideration by the authorities before issuing a final notification”.

26. *“In the result, we hold that the impugned notification dated 26.07.2013 is not sustainable in law and, therefore, quashed and set aside. Rule is, therefore, made absolute in the aforesaid terms with no orders as to costs.”*

The Applicant had filed objections which were duly considered by the MoEF&CC and even the Applicant was heard. There is nothing on record before us that would show that there is no application of mind and that the objections were not considered objectively by the MoEF&CC. In light of this, we are unable to accept this contention raised on behalf of the Applicants.

29. The other argument of the Applicant which deserves to be considered with some merit is that the final impugned Notification is at substantial variance to the draft Notification. This has not only resulted in prejudice to the environment but has also defeated the purpose of Rule 5(3) of the Environment (Protection) Rules, 1986. Following are few examples of such variance and which have significant effect on the environmental laws:

- (a). The exclusion of application of the Water Act and the Air Act was never proposed or stated in the draft Notification, while it has been introduced in the final Notification.
- (b). Role of the State Pollution Control Boards to monitor and verify the environmental conditions is eliminated in the final notification. The construction of built up area upto area of 20,000 sq. meter upto 1,50,000 sq. meter which were

otherwise covered under the Act of 1986 now have been brought under the State Laws without specifying them in the draft notification. The draft Notification specifically mentions that the exclusion/amendment benefits mentioned in the draft Notification are not intended for hospitals whereas the final notification clearly excludes hospitals from the purview of the EIA Notification, 2006 and Environment (Protection) Act, 1986. It is at substantial variance as the hospitals fall under red category under the Central Pollution Control Board categorization dated 7th March, 2016. So, provision of dealing with the environmental conditions of hospitals falling under the environmental norms.

- (C). Addition of Appendix XV, accreditation of environmental auditor (Qualified Building Environment Auditor).
- (D). Addition of Appendix XVI, Environmental Cell at the level of local authority.

On the above premises, it is contended that on the one hand, there is substantial difference between the draft and the final notifications while on the other hand Applicants were deprived of the right to file objections on these aspects. Reliance is placed on the judgement of the Hon'ble Supreme Court of India in the case of *State of Punjab vs. Tehal Singh & Ors*, AIR 2002 SC 533 wherein the Supreme Court held that Principle of Natural Justice to subordinate legislation may be applied but where the legislature provides an

opportunity of hearing and filing objections then it must be adhered to *sensu stricto*.

30. From the records before the Tribunal, it is clear that there are variations even of substantial nature between the draft and the final Notification dated 9th December, 2016 issued by the respondent. One of the significant failures of the same is that the applicants or public at large has lost substantive right to file objections on these aspects to the draft Notification. They have also lost the right to be heard in terms of Rule 5(3) of the Rules of 1986. Incorporation of such provisions from the draft Notification into the final Notification would not be permissible.

31. Some of the portions of the impugned Notification; particularly, relating to granting of exemption from the application of Water and Air Acts; Rendering the provisions of the central law for taking action, penalizing defaulters and offenders of the environmental law being rendered ineffective; ambiguity and deficiencies in constitution of the Environmental Cell are some of the patent features of the impugned Notification which dilutes the environmental impacts on the one hand, while on the other, they are in derogation to India's international commitments to the Rio Declaration, 1992 and Paris Agreement, 2015. If principle 15 to 17 of the Rio Declaration is read along with clauses of the Paris Agreement, 2015, particularly, in face of precautionary approach, preventing irreparable damage forming definite environmental impact assessment to examine adverse impact on the environment, reduction on the growth of is carbon emission and to adopt best practices and achieve the ambitious targets between

the stipulated time then the adopting cumulative effect of the Notification dated 9th December, 2016 would have some element of derogation. The Notification also ignores some essential features like source of water, source of raw material, urban ecology, provision of no development zone and construction face impacts. These aspects have a direct bearing on protection of environment and keeping in line with the Principle of Sustainable Development. It is important that there should be development and particularly, when the development is guided by the social cause but that development should not be permitted to cause irreparable loss to the environment and ecology. Sustainable development has to be the ultimate criteria. The Hon'ble Supreme Court in the case of *N.D. Dayal v. Union of India*, (2004) 9 SCC 362 deliberated upon the Doctrine of Sustainable Development and while comparing with the economic growth and well being held as under:

“24.The right to development cannot be treated as a mere right to economic betterment or cannot be limited to as a misnomer to simple construction activities. The right to development encompasses much more than economic well being, and includes within its definition the guarantee of fundamental human rights. The 'development' is not related only to the growth of GNP. In the classic work - '*Development As Freedom*' the Nobel prize winner Amartya Sen pointed out that 'the issue of development cannot be separated from the conceptual framework of human right'. This idea is also part of the UN Declaration on the Right to Development. The right to development includes the whole spectrum of civil, cultural, economic, political and social process, for the improvement of peoples' well being and realization of their full potential. It is an integral part of human right. Of course, construction of a dam or a mega project is definitely an attempt to achieve the goal of wholesome development. Such works could very well be treated as integral component for development.

25. Therefore, the adherence of sustainable development principle is a sine qua non for the maintenance of the symbiotic balance between the rights to environment and development. Right to environment is a fundamental right. On the other hand right to development is also one. Here the right to 'sustainable development' cannot be singled out. Therefore, the concept of 'sustainable development' is to be treated an integral part of 'life' under Article 21. The weighty concepts like intergenerational equity (*State of Himachal Pradesh v. Ganesh Wood Products*, [1995] 6 SCC 363), public trust doctrine (*MC Mehta v. Kamal Nath*, [1997] 1 SCC 388) and precautionary principle (*Vellore Citizens*), which we declared as inseparable ingredients of our environmental jurisprudence, could only be nurtured by ensuring sustainable development.

26. To ensure sustainable development is one of the goals of Environmental Protection Act, 1986 (for short 'the Act') and this is quiet necessary to guarantee 'right to life' under Article 21. If the Act is not armed with the powers to ensure sustainable development, it will become a barren shell. In other words, *sustainable development is one of the means to achieve the object and purpose of the Act as well as the protection of 'life' under Article 21.* Acknowledgment of this principle will breath new life into our environmental jurisprudence and constitutional resolve. Sustainable development could be achieved only by strict compliance of the directions under the Act. The object and purpose of the Act-"to provide for the protection and improvement of environment" could only be achieved by ensuring the strict compliance of its directions. The concerned authorities by exercising its powers under the Act will have to ensure the acquiescence of sustainable development. Therefore, the directions or conditions put forward by the Act need to be strictly complied with. Thus the power under the Act cannot be treated as a power simpliciter, but it is a power coupled with duty. It is the duty of the State to make sure the fulfilment of conditions or direction under the Act. Without strict compliance, right to environment under Article 21 could not be guaranteed and the purpose of the Act will also be defeated. The commitment to the conditions thereof is an obligation both under Article 21 and under the Act. The conditions glued to the environmental clearance for the Tehri Dam Project given by the Ministry of Environment vide its Order dated July 19, 1990 has to be viewed from this perspective”.

Despite the above shortcomings of the Notification and some clauses suffering from legal infirmity, the impugned Notification has certainly good and effective aspects as well. As already noticed by us, it brings into effect a social cause of providing affordable housing to the poor strata of the society. It also proposes to decentralize and bring authorities granting environmental clearance and those granting building permission together under a single window system so as to address environmental concerns. The concept of one window system is sought to be introduced. The Notification specifically provides for emphasis on the aspects that are required to be considered by the environmental cell with special focus on energy use, energy generated on site from on site renewable energy sources, water use and waste water generated, treated on site, waste segregated and treated on site, waste segregation and treated on site, tree plantation and maintenance. These are the few good features of the Notification which also do not suffer from element of illegality. 'Housing for all by 2022' is a purpose and object in conformity with the constitutional mandate. There would be collective and coordinated effort by the Environmental Cell, local and other authorities at the State level to expeditiously deal with environmental clearance.

ORDER/DIRECTIONS

32. The object of the Notification is laudable that is providing housing to the poor. The provisions of the existing regime under the Regulation/Notification of 2006 are sought to be liberalized and expanded for obtaining that object. Some of the provisions of the Notification are being amended to provide for decentralized regulation

in relation to building projects. Certain specified building and construction projects of specified area are proposed to be exempted from the rigours of the Notification. But these amendments would have to be in consonance with the law, where certain provisions of the amended Notification dated 9th December, 2016 are in consonance with the provisions of the Act of 1986 and do not suffer from the *vires* of illegality. Thus, some other provisions of the same Notification *ex-facie* suffer from legal infirmities and are incapable of being implemented in accordance with the scheme of federal structure under the Constitution of India. Out of them, some provisions are directly opposed to the Principle of Non-regression as they considerably dilute the existing environmental laws and standards to the prejudice of the environment. Thus, in the facts and circumstances of the present case, the Tribunal can safely take recourse to the doctrine of severability to declare some of the provisions of the Notification as *ultra-vires* or ineffective while holding the other part of the Notification as legally sound and sustainable.

33. In view of the above, we pass the following order/directions:

1. We hold and declare that this Tribunal has jurisdiction to examine the legality, validity and correctness of a Notification issued by the competent forum in exercise of its power of subordinate legislation with regard to acts stated in Schedule-I to the National Green Tribunal Act, 2010.
2. We hold and declare that (i) clause 14(8), (ii) the provisions relating to exclusion of Consent to Operate and Consent to Establish under Water (Prevention and Control of Pollution)

Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 in clause 14 of the impugned Notification; (iii) Appendix-XVI relating to constitution and functioning of Environmental Cell, cannot be sustained and are liable to be quashed for the reasons afore-stated. Thus, we direct MoEF&CC to re-examine its Notification dated 9th December, 2016 and take appropriate steps to delete, amend and rectify the clauses of the said Notification in light of this judgement.

3. As a result of the above, the byelaws amended by the DDA vide its Notification dated 22nd March, 2016 can also not be given effect to, unless the Notification dated 9th December, 2016 is amended in terms of this judgement.
4. Till the time the Ministry comply with the above directions and notify the amended provisions of Regulations of 2006, it will not implement the impugned Notifications. However, once the amended regulations are notified, MoEF&CC/SEIAA /Local Authorities can give effect to that, without any further reference to the Tribunal.
5. MoEF&CC shall, particularly take care that the laudable social cause of 'providing Housing to the poor' does not get defeated by business, economic profitability with reference to 'ease of doing business', while particularly protecting the environment.

34. With the above order/directions, the Original Applications No. 677 of 2016, 01 of 2017, 07 of 2017, 55 of 2017 and 67 of 2017 stand disposed of, with no order as to costs.

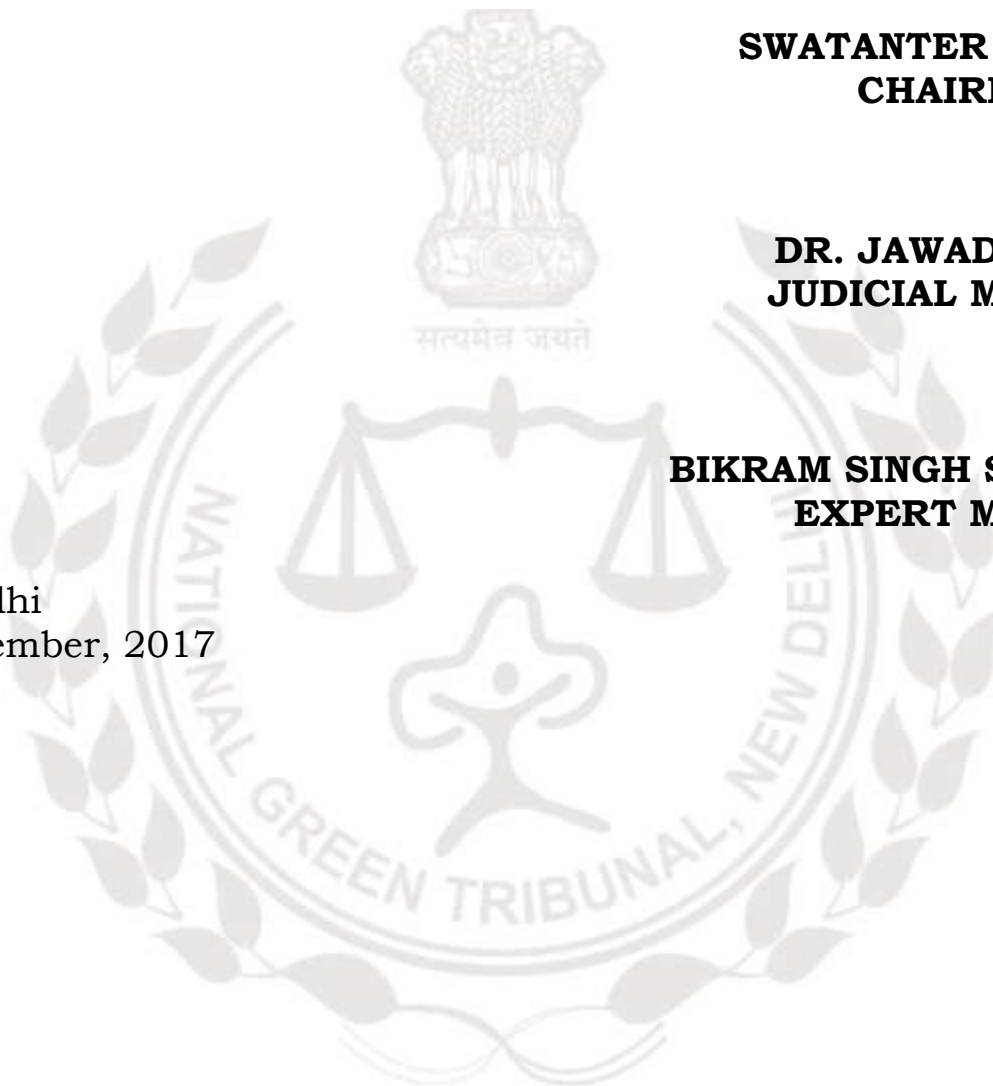
35. All the Miscellaneous Applications No. 148 of 2017, 03 of 2017, 445 of 2017, 879 of 2017 and 620 of 2017 have become infructuous and are accordingly disposed of.

**SWATANTER KUMAR
CHAIRPERSON**

**DR. JAWAD RAHIM
JUDICIAL MEMBER**

**BIKRAM SINGH SAJWAN
EXPERT MEMBER**

New Delhi
8th December, 2017



NGT

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

Tel. No.: 22793132

No. NGT- 2017/CR-45/SEIAA
Environment Department,
Mantralaya, Mumai-400 032.
Dated : 29 January, 2018.

C I R C U L A R

Sub : Clarification regarding appraisal of cases for grant of Environment Clearance under provisions of the EIA Notification dtd. 14.9.2006 in light of the order passed by Hon'ble NGT, WZ, Pune and opinion given by the Law & Judiciary Department.

The Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India had made several amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 by issuing notification dtd 9th December, 2016.

The said notification dtd. 9th December, 2016 was challenged before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi by filling Original Application Nos. 677 of 2016, 01 of 2017, 07 of 2017 and 55 of 2017, which has been decided by the Hon'ble Tribunal by passing an order dtd. 8.12.2017.

The Environment Department, Government of Maharashtra has obtained legal opinion from the Law & Judiciary Department, Government of Maharashtra on following two points w.r. to the order dtd. 8.12.2017 passed by the Hon'ble Tribunal :

- (a) whether the provisions of the EIA Notification dtd. 14.9.2006 amended prior 9th December, 2016 stands applicable and can be implementable by SEACs and SEIAA now?
- (b) whether the SEIAA / SEAC can appraise applications for grant of prior Environment Clearance received from the project proponents as per the provisions of EIA Notification, 2006 amended prior 9th December, 2016 till further notification is issued by the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India in compliance with the aforesaid Judgement?

The Law & Judiciary Department has opined that (related paras of the opinion are reproduced hereunder) :

- (a) *"the un-amended provisions of EIA Notification, 2006 are in force and can be implemented by SEACs and SEIAA,*
- (b) *Pre-9th December, 2016 amendment, Notification 2006 can be implemented by authorities concerned assuming that paragraph no.14 (which was inserted by 2016 amendment) is not at all inserted.*
- (c) *Regarding substitution of item no.8 and entries relating thereto in the schedule to the Notification 2006, the SEIAA/SEAC can appraise the applications for grant of prior environmental clearance, in accordance with un-amended provisions of the Notification 2006."*

Considering above opinion given by the Law & Judiciary Department, concerned SEACs / SEIAA are directed to implement provisions of the EIA Notification dtd. 14.9.2006, until further orders of the M.o.E.F. & C.C. , G.o.I. w.r. to the amendment in the Notification dtd. 9.12.2016 in terms of the Judgement passed by the Hon'ble Tribunal dtd. 8.12.2017.

All Municipal Corporations, Municipal Councils and all Special Planning Authorities in Pune and Kokan Division to take note that they **shall not process** any permission to building and construction projects $\geq 20,000$ sq.m. and $< 1,50,000$ sq.m. BUA by integrating environmental clearance conditions w.r. to the amendment dtd. 9.12.2016 in the EIA Notification 2006. The powers originally vested with the SEACs / SEIAA under provisions of the EIA Notification dtd. 14.9.2006 are in force in the light of the aforesaid Judgement. Hence, all concerned local bodies / Authorities are directed to inform concerned Project Proponents to apply online to the website www.ecmpcb.in for grant of Environment Clearance.


(Satish M. Gavai)

Addl. Chief Secretary,
Environment Department

Copy forwarded to :

- 1) Addl. Chief Secretary to Chief Minister, Maharashtra State – for information.
- 2) Chairman, State Environment Impact Assessment Authority / State Level Expert Appraisal Committee – I/ II/ III – for information.
- 3) P.S. to Hon'ble Minister (Environment) – for information.
- 4) P.S. to Hon'ble State Minister (Environment) – for information.

Copy to :

- 1) Additional Chief Secretary, Revenue Department – for information – It is requested to forward the above Circular to the Concerned Authorities under your jurisdiction.
- 2) Principal Secretary – I / II, Urban Development Department – for information – It is requested to forward the above Circular to the Planning Authorities under your jurisdiction.
- 3) Member Secretary, State Level Expert Appraisal Committee – I/ II/ III, 15th Floor, New Administrative Building, Mantralaya – for information and necessary action.
- 4) Divisional Commissioner – Konkan / Nashik / Pune / Aurangabad / Amravati / Nagpur – for information and necessary action.
- 5) Municipal Commissioner – Municipal Corporation of Greater Mumbai / Navi Mumbai Municipal Corporation / Thane Municipal Corporation / Pune Municipal Corporation / Pimpri- Chinchwad Municipal Corporation / Solapur Municipal Corporation / Sangli-Miraj-Kupwad Municipal Corporation / Kolhapur Municipal Corporation / Nashik Municipal Corporation / Aurangabad Municipal Corporation / Nagpur Municipal Corporation / Amravati Municipal Corporation / Ulhasnagar Municipal Corporation / Kalyan Dombivali Municipal Corporation / Nanded – Waghala Municipal Corporation / Bhiwandi-Nijampur Municipal Corporation / Panvel Municipal Corporation / Akola Municipal Corporation / Malegaon Municipal Corporation / Mira-Bhyandar Municipal Corporation / Jalgaon

Municipal Corporation / Dhule Municipal Corporation / Ahamadnagar Municipal Corporation / Vasai-Virar Municipal Corporation / Parabhani Municipal Corporation / Chandrapur Municipal Corporation / Latur Municipal Corporation – for information and necessary action

- 6) Managing Director, CIDCO / MIDC – for information and necessary action.
- 7) Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority – for information and necessary action.
- 8) Vice-Chairman & Managing Director, Maharashtra State Road Development Corporation - for information and necessary action.
- 9) Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority, Anant Kanekar Marg, Bandra (E), Mumbai – 400 051 – for information and necessary action
- 10) Member Secretary, Maharashtra Pollution Control Board, Sion (E), Mumbai – for information .

**(Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, and Section 3, Sub-section (ii))
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

New Delhi 14th September, 2006

Notification

S.O. 1533 Whereas, a draft notification **under sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for imposing** certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the Schedule to the notification, being undertaken in any part of India¹, unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of National Environment Policy **as approved by the Union Cabinet on 18th May, 2006** and the procedure specified in the notification, by the Central Government or the State or Union territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), to be constituted by the Central Government in consultation with the State Government or the Union territory Administration concerned under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of this notification, was published in the Gazette of India ,Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1324 (E) dated the 15th September ,2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15th September, 2005;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification.

¹Includes the territorial waters

2. Requirements of prior Environmental Clearance (EC):- The following projects or activities shall require prior environmental clearance from the concerned regulatory authority, which shall hereinafter referred to be as the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for matters falling under Category 'B' in the said Schedule, before any construction work, or preparation of land by the project management except for securing the land, is started on the project or activity:

- (i) All new projects or activities listed in the Schedule to this notification;
- (ii) Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization;
- (iii) Any change in product - mix in an existing manufacturing unit included in Schedule beyond the specified range.

3. State Level Environment Impact Assessment Authority:- (1) A State Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the SEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of three Members including a Chairman and a Member – Secretary to be nominated by the State Government or the Union territory Administration concerned.

- (2) The Member-Secretary shall be a serving officer of the concerned State Government or Union territory administration familiar with environmental laws.
- (3) The other two Members shall be either a professional or expert fulfilling the eligibility criteria given in Appendix VI to this notification.
- (4) One of the specified Members in sub-paragraph (3) above who is an expert in the Environmental Impact Assessment process shall be the Chairman of the SEIAA.
- (5) The State Government or Union territory Administration shall forward the names of the Members and the Chairman referred in sub- paragraph 3 to 4 above to the Central Government and the Central Government shall constitute the SEIAA as an authority for the purposes of this notification within thirty days of the date of receipt of the names.
- (6) The non-official Member and the Chairman shall have a fixed term of three years (from the date of the publication of the notification by the Central Government constituting the authority).
- (7) All decisions of the SEIAA shall be unanimous and taken in a meeting.

4. Categorization of projects and activities:-

- (i) All projects and activities are broadly categorized in to two categories - Category A and Category B, based on the spatial extent of potential impacts and potential impacts on human health and natural and man made resources.

(ii) All projects or activities included as Category 'A' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities and change in product mix, shall require prior environmental clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests (MoEF) on the recommendations of an Expert Appraisal Committee (EAC) to be constituted by the Central Government for the purposes of this notification;

(iii) All projects or activities included as Category 'B' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities as specified in sub paragraph (ii) of paragraph 2, or change in product mix as specified in sub paragraph (iii) of paragraph 2, but excluding those which fulfill the General Conditions (GC) stipulated in the Schedule, *will* require prior environmental clearance from the State/Union territory Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). The SEIAA shall base its decision on the recommendations of a State or Union territory level Expert Appraisal Committee (SEAC) as to be constituted for in this notification. In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project;

5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government and SEACs (hereinafter referred to as the (EAC) and (SEAC) at the State or the Union territory level shall screen, scope and appraise projects or activities in Category 'A' and Category 'B' respectively. EAC and SEAC's shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union territory Administration with identical composition;

(b) The Central Government may, with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administrations, constitutes one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost;

(c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years;

(d) The authorised members of the EAC and SEAC, concerned, may inspect any site(s) connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought, for the purposes of screening or scoping or appraisal, with prior notice of at least seven days to the applicant, who shall provide necessary facilities for the inspection;

(e) The EAC and SEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. The applicant shall furnish, along with the application, a copy of the pre-feasibility project report except that, in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule) in addition to Form 1 and the Supplementary Form 1A, a copy of the conceptual plan shall be provided, instead of the pre-feasibility report.

7. Stages in the Prior Environmental Clearance (EC) Process for New Projects:-

7(i) The environmental clearance process for new projects will comprise of a maximum of four stages, all of which may not apply to particular cases as set forth below in this notification. These four stages in sequential order are:-

- Stage (1) Screening (Only for Category 'B' projects and activities)
- Stage (2) Scoping
- Stage (3) Public Consultation
- Stage (4) Appraisal

I. Stage (1) - Screening:

In case of Category 'B' projects or activities, this stage will entail the scrutiny of an application seeking prior environmental clearance made in Form 1 by the concerned State level Expert Appraisal Committee (SEAC) for determining whether or not the project or activity requires further environmental studies for preparation of an Environmental Impact Assessment (EIA) for its appraisal prior to the grant of environmental clearance depending up on the nature and location specificity of the project . The projects requiring an Environmental Impact Assessment report shall be termed Category 'B1' and remaining projects shall be termed Category 'B2' and will not require an Environment Impact Assessment report. For categorization of projects into B1 or B2 except item 8 (b), the Ministry of Environment and Forests shall issue appropriate guidelines from time to time.

II. Stage (2) - Scoping:

(i) "Scoping": refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category 'A' projects or activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1' projects or activities, including applications for expansion and/or modernization and/or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms Of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. The Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the Terms of Reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form1/Form 1A including Terms of Reference proposed by the applicant, a site visit by a sub- group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, Terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. All projects and activities listed as Category 'B' in Item 8 of the Schedule (Construction/Township/Commercial Complexes /Housing) shall not require Scoping and will be appraised on the basis of Form 1/ Form 1A and the conceptual plan.

(ii) The Terms of Reference (TOR) shall be conveyed to the applicant by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as concerned within sixty days of the receipt of Form 1. In the case of Category A Hydroelectric projects Item 1(c) (i) of the Schedule the Terms of Reference shall be conveyed along with the clearance for pre-construction activities .If the Terms of Reference are not finalized and conveyed to the applicant within sixty days of the receipt of Form 1, the Terms of Reference suggested by the applicant shall be deemed as the final Terms of Reference approved for the EIA studies. The approved Terms of

Reference shall be displayed on the website of the Ministry of Environment and Forests and the concerned State Level Environment Impact Assessment Authority.

(iii) Applications for prior environmental clearance may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned at this stage itself. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

III. Stage (3) - Public Consultation:

(i) “Public Consultation” refers to the process by which the concerns of local affected persons and others who have plausible stake in the environmental impacts of the project or activity are ascertained with a view to taking into account all the material concerns in the project or activity design as appropriate. All Category ‘A’ and Category B1 projects or activities shall undertake Public Consultation, except the following:-

- (a) modernization of irrigation projects (item 1(c) (ii) of the Schedule).
- (b) all projects or activities located within industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals.
- (c) expansion of Roads and Highways (item 7 (f) of the Schedule) which do not involve any further acquisition of land.
- (d) all Building /Construction projects/Area Development projects and Townships (item 8).
- (e) all Category ‘B2’ projects and activities.
- (f) all projects or activities concerning national defence and security or involving other strategic considerations as determined by the Central Government.

(ii) The Public Consultation shall ordinarily have two components comprising of:-

(a) a public hearing at the site or in its close proximity- district wise, to be carried out in the manner prescribed in Appendix IV, for ascertaining concerns of local affected persons;

(b) obtain responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity.

(iii) the public hearing at, or in close proximity to, the site(s) in all cases shall be conducted by the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) concerned in the specified manner and forward the proceedings to the regulatory authority concerned within 45(forty five) of a request to the effect from the applicant.

(iv) in case the State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee concerned does not undertake and complete the public hearing within the specified period, and/or does not convey the proceedings of the public hearing within the prescribed period

directly to the regulatory authority concerned as above, the regulatory authority shall engage another public agency or authority which is not subordinate to the regulatory authority, to complete the process within a further period of forty five days,.

(v) If the public agency or authority nominated under the sub paragraph (iii) above reports to the regulatory authority concerned that owing to the local situation, it is not possible to conduct the public hearing in a manner which will enable the views of the concerned local persons to be freely expressed, it shall report the facts in detail to the concerned regulatory authority, which may, after due consideration of the report and other reliable information that it may have, decide that the public consultation in the case need not include the public hearing.

(vi) For obtaining responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity, the concerned regulatory authority and the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) shall invite responses from such concerned persons by placing on their website the Summary EIA report prepared in the format given in Appendix IIIA by the applicant along with a copy of the application in the prescribed form, within seven days of the receipt of a written request for arranging the public hearing. Confidential information including non-disclosable or legally privileged information involving Intellectual Property Right, source specified in the application shall not be placed on the web site. The regulatory authority concerned may also use other appropriate media for ensuring wide publicity about the project or activity. The regulatory authority shall, however, make available on a written request from any concerned person the Draft EIA report for inspection at a notified place during normal office hours till the date of the public hearing. All the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the applicant through the quickest available means.

(vii) After completion of the public consultation, the applicant shall address all the material environmental concerns expressed during this process, and make appropriate changes in the draft EIA and EMP. The final EIA report, so prepared, shall be submitted by the applicant to the concerned regulatory authority for appraisal. The applicant may alternatively submit a supplementary report to draft EIA and EMP addressing all the concerns expressed during the public consultation.

IV. Stage (4) - Appraisal:

(i) Appraisal means the detailed scrutiny by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee of the application and other documents like the Final EIA report, outcome of the public consultations including public hearing proceedings, submitted by the applicant to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance. This appraisal shall be made by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned in a transparent manner in a proceeding to which the applicant shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative. On conclusion of this proceeding, the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall make categorical recommendations to the regulatory authority concerned either for grant of prior environmental clearance on stipulated terms and conditions, or rejection of the application for prior environmental clearance, together with reasons for the same.

(ii) The appraisal of all projects or activities which are not required to undergo public consultation, or submit an Environment Impact Assessment report, shall be carried out on the basis of the prescribed application Form 1 and Form 1A as applicable, any other relevant

validated information available and the site visit wherever the same is considered as necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iii) The appraisal of an application shall be completed by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within sixty days of the receipt of the final Environment Impact Assessment report and other documents or the receipt of Form 1 and Form 1 A, where public consultation is not necessary and the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall be placed before the competent authority for a final decision within the next fifteen days. The prescribed procedure for appraisal is given in Appendix V ;

7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:

All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects or for the modernization of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product –mix shall be made in Form I and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence necessary including preparation of EIA and public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

8. Grant or Rejection of Prior Environmental Clearance (EC):

(i) The regulatory authority shall consider the recommendations of the EAC or SEAC concerned and convey its decision to the applicant within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned or in other words within one hundred and five days of the receipt of the final Environment Impact Assessment Report, and where Environment Impact Assessment is not required, within one hundred and five days of the receipt of the complete application with requisite documents, except as provided below.

(ii) The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty days.

(iii) In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the

applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iv) On expiry of the period specified for decision by the regulatory authority under paragraph (i) and (ii) above, as applicable, the decision of the regulatory authority, and the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be public documents.

(v) Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

(vi) Deliberate concealment and/or submission of false or misleading information or data which is material to screening or scoping or appraisal or decision on the application shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior environmental clearance granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior environmental clearance already granted, on such ground, shall be decided by the regulatory authority, after giving a personal hearing to the applicant, and following the principles of natural justice.

9. Validity of Environmental Clearance (EC):

The “Validity of Environmental Clearance” is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub paragraph (iv) of paragraph 7 above, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects (item 1(c) of the Schedule), project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects and activities. However, in the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer. This period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of five years provided an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form 1, and Supplementary Form 1A, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule). In this regard the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be.

10. Post Environmental Clearance Monitoring:

(i) It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year.

(ii) All such compliance reports submitted by the project management shall be public documents. Copies of the same shall be given to any person on application to the concerned regulatory authority. The latest such compliance report shall also be displayed on the web site of the concerned regulatory authority.

11. Transferability of Environmental Clearance (EC):

A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written “no objection” by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

12. Operation of EIA Notification, 1994, till disposal of pending cases:

From the date of final publication of this notification the Environment Impact Assessment (EIA) notification number S.O.60 (E) dated 27th January, 1994 is hereby superseded, except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression to the extent that in case of all or some types of applications made for prior environmental clearance and pending on the date of final publication of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification except the list of the projects or activities requiring prior environmental clearance in Schedule I, or continue operation of some or all provisions of the said notification, for a period not exceeding one year from the date of issue of this notification.

[No. J-11013/56/2004-IA-II (I)]

(R.CHANDRAMOHAN)
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

SCHEDULE

(See paragraph 2 and 7)

LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1		Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(a)	Mining of minerals	≥ 50 ha. of mining lease area Asbestos mining irrespective of mining area	<50 ha ≥ 5 ha .of mining lease area.	General Condition shall apply <u>Note</u> Mineral prospecting (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey
1(b)	Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production	All projects		<u>Note</u> Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey
1(c)	River Valley projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area	(i) < 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation; (ii) < 10,000 ha. of culturable command area	General Condition shall apply
1(d)	Thermal Power Plants	≥ 500 MW (coal/lignite/naptha & gas based); ≥ 50 MW (Pet coke diesel and all other fuels -)	< 500 MW (coal/lignite/naptha & gas based); <50 MW ≥ 5MW (Pet coke ,diesel and all other fuels)	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(e)	Nuclear power projects and processing of nuclear fuel	All projects	-	
2		Primary Processing		
2(a)	Coal washeries	≥ 1 million ton/annum throughput of coal	<1million ton/annum throughput of coal	General Condition shall apply (If located within mining area the proposal shall be appraised together with the mining proposal)
2 (b)	Mineral beneficiation	≥ 0.1million ton/annum mineral throughput	< 0.1million ton/annum mineral throughput	General Condition shall apply (Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance)

3		Materials Production		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)	<p>a)Primary metallurgical industry All projects</p> <p>b) Sponge iron manufacturing ≥ 200TPD</p> <p>c)Secondary metallurgical processing industry</p> <p>All toxic and heavy metal producing units ≥ 20,000 tonnes /annum</p> <p>-</p>	<p>Sponge iron manufacturing <200TPD</p> <p>Secondary metallurgical processing industry</p> <p>i.)All toxic and heavy metal producing units <20,000 tonnes /annum</p> <p>ii.)All other non –toxic secondary metallurgical processing industries >5000 tonnes/annum</p>	General Condition shall apply for Sponge iron manufacturing
3(b)	Cement plants	≥ 1.0 million tonnes/annum production capacity	<1.0 million tonnes/annum production capacity. All Stand alone grinding units	General Condition shall apply

4		Materials Processing		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4(a)	Petroleum refining industry	All projects	-	-
4(b)	Coke oven plants	≥2,50,000 tonnes/annum -	<2,50,000 & ≥25,000 tonnes/annum	-
4(c)	Asbestos milling and asbestos based products	All projects	-	-
4(d)	Chlor-alkali industry	≥300 TPD production capacity or a unit located outside the notified industrial area/estate	<300 TPD production capacity and located within a notified industrial area/estate	Specific Condition shall apply No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempted from this Notification
4(e)	Soda ash Industry	All projects	-	-
4(f)	Leather/skin/hide processing industry	New projects outside the industrial area or expansion of existing units outside the industrial area	All new or expansion of projects located within a notified industrial area/estate	Specific condition shall apply
5		Manufacturing/Fabrication		
5(a)	Chemical fertilizers	All projects	-	-
5(b)	Pesticides industry and pesticide specific intermediates (excluding formulations)	All units producing technical grade pesticides	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(c)	Petro-chemical complexes (industries based on processing of petroleum fractions & natural gas and/or reforming to aromatics)	All projects -	-	-
5(d)	Manmade fibres manufacturing	Rayon	Others	General Condition shall apply
5(e)	Petrochemical based processing (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes)	Located out side the notified industrial area/ estate -	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	Located out side the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(g)	Distilleries	(i) All Molasses based distilleries (ii) All Cane juice/ non-molasses based distilleries ≥ 30 KLD	All Cane juice/non-molasses based distilleries - < 30 KLD	General Condition shall apply
5(h)	Integrated paint industry	-	All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(i)	Pulp & paper industry excluding manufacturing of paper from waste paper and manufacture of paper from ready pulp with out bleaching	Pulp manufacturing and Pulp& Paper manufacturing industry -	Paper manufacturing industry without pulp manufacturing	General Condition shall apply
5(j)	Sugar Industry	- -	≥ 5000 tcd cane crushing capacity	General Condition shall apply
5(k)	Induction/arc furnaces/cupola furnaces 5TPH or more	- -	All projects	General Condition shall apply
6		Service Sectors		
6(a)	Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks /sanctuaries/coral reefs /ecologically sensitive areas including LNG Terminal	All projects -		-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6(b)	Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000)	-	All projects	General Condition shall apply
7		Physical Infrastructure including Environmental Services		
7(a)	Air ports	All projects	-	-
7(b)	All ship breaking yards including ship breaking units	All projects	-	-
7(c)	Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes.	<p>If at least one industry in the proposed industrial estate falls under the Category A, entire industrial area shall be treated as Category A, irrespective of the area.</p> <p>Industrial estates with area greater than 500 ha. and housing at least one Category B industry.</p>	<p>-Industrial estates housing at least one Category B industry and area <500 ha.</p> <p>Industrial estates of area > 500 ha. and not housing any industry belonging to Category A or B.</p>	<p>Special condition shall apply</p> <p>Note: Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance.</p>
7(d)	Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)	All integrated facilities having incineration & landfill or incineration alone	All facilities having land fill only	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7(e)	Ports, Harbours	≥ 5 million TPA of cargo handling capacity (excluding fishing harbours)	< 5 million TPA of cargo handling capacity and/or ports/ harbours ≥10,000 TPA of fish handling capacity	General Condition shall apply
7(f)	Highways	i) New National High ways; and ii) Expansion of National High ways greater than 30 KM, involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition and passing through more than one State.	i) New State High ways; and ii) Expansion of National / State Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.	General Condition shall apply
7(g)	Aerial ropeways		All projects	General Condition shall apply
7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)		All projects	General Condition shall apply
7(i)	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)		All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		Building /Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of built-up area#	#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)
8(b)	Townships and Area Development projects.		Covering an area ≥ 50 ha and or built up area ≥1,50,000 sq .mtrs ++	++All projects under Item 8(b) shall be appraised as Category B1

Note:-

General Condition (GC):

Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries.

Specific Condition (SC):

If any Industrial Estate/Complex / Export processing Zones /Special Economic Zones/Biotech Parks / Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre –defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates /complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/estate).

APPENDIX I

(See paragraph – 6)

FORM 1

(I) Basic Information

Name of the Project:

Location / site alternatives under consideration:

Size of the Project: *

Expected cost of the project:

Contact Information:

Screening Category:

- *Capacity corresponding to sectoral activity (such as production capacity for manufacturing, mining lease area and production capacity for mineral production, area for mineral exploration, length for linear transport infrastructure, generation capacity for power generation etc.,)*

(II) Activity

1. **Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)**

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
1.1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan)		
1.2	Clearance of existing land, vegetation and buildings?		
1.3	Creation of new land uses?		
1.4	Pre-construction investigations e.g. bore houses, soil testing?		
1.5	Construction works?		

1.6	Demolition works?		
1.7	Temporary sites used for construction works or housing of construction workers?		
1.8	Above ground buildings, structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations		
1.9	Underground works including mining or tunneling?		
1.10	Reclamation works?		
1.11	Dredging?		
1.12	Offshore structures?		
1.13	Production and manufacturing processes?		
1.14	Facilities for storage of goods or materials?		
1.15	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents?		
1.16	Facilities for long term housing of operational workers?		
1.17	New road, rail or sea traffic during construction or operation?		
1.18	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc?		
1.19	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?		
1.20	New or diverted transmission lines or pipelines?		
1.21	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of watercourses or aquifers?		
1.22	Stream crossings?		
1.23	Abstraction or transfers of water from ground or surface waters?		
1.24	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?		

1.25	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?		
1.26	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works?		
1.27	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?		
1.28	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?		
1.29	Introduction of alien species?		
1.30	Loss of native species or genetic diversity?		
1.31	Any other actions?		

2. Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):

S.No.	Information/checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
2.1	Land especially undeveloped or agricultural land (ha)		
2.2	Water (expected source & competing users) unit: KLD		
2.3	Minerals (MT)		
2.4	Construction material – stone, aggregates, and / soil (expected source – MT)		
2.5	Forests and timber (source – MT)		
2.6	Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit: fuel (MT), energy (MW)		
2.7	Any other natural resources (use appropriate standard units)		

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
3.1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
3.2	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)		
3.3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
3.4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.,		
3.5	Any other causes		

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
4.1	Spoil, overburden or mine wastes		
4.2	Municipal waste (domestic and or commercial wastes)		
4.3	Hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules)		

4.4	Other industrial process wastes		
4.5	Surplus product		
4.6	Sewage sludge or other sludge from effluent treatment		
4.7	Construction or demolition wastes		
4.8	Redundant machinery or equipment		
4.9	Contaminated soils or other materials		
4.10	Agricultural wastes		
4.11	Other solid wastes		

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
5.1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
5.2	Emissions from production processes		
5.3	Emissions from materials handling including storage or transport		
5.4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5.5	Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste		

5.6	Emissions from incineration of waste		
5.7	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)		
5.8	Emissions from any other sources		

6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data with source of information data
6.1	From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers		
6.2	From industrial or similar processes		
6.3	From construction or demolition		
6.4	From blasting or piling		
6.5	From construction or operational traffic		
6.6	From lighting or cooling systems		
6.7	From any other sources		

7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
7.1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
7.2	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge)		
7.3	By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water		
7.4	From any other sources		
7.5	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		

8. Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
8.1	From explosions, spillages, fires etc from storage, handling, use or production of hazardous substances		
8.2	From any other causes		
8.3	Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g. floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)?		

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
9.1	<p>Lead to development of supporting. lities, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.) • housing development • extractive industries • supply industries • other 		
9.2	Lead to after-use of the site, which could have an impact on the environment		
9.3	Set a precedent for later developments		
9.4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		

(III) Environmental Sensitivity

S.No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value		

2	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests		
3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration		
4	Inland, coastal, marine or underground waters		
5	State, National boundaries		
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas		
7	Defence installations		
8	Densely populated or built-up area		
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses (<i>hospitals, schools, places of worship, community facilities</i>)		
10	Areas containing important, high quality or scarce resources (<i>ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals</i>)		
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (<i>those where existing legal environmental standards are exceeded</i>)		
12	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (<i>earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions</i>)		

(IV). Proposed Terms of Reference for EIA studies

APPENDIX II

(See paragraph 6)

FORM-1 A (only for construction projects listed under item 8 of the Schedule)

CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)

1. LAND ENVIRONMENT

(Attach panoramic view of the project site and the vicinity)

1.1. Will the existing landuse get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Proposed landuse must conform to the approved Master Plan / Development Plan of the area. Change of landuse if any and the statutory approval from the competent authority be submitted). Attach Maps of (i) site location, (ii) surrounding features of the proposed site (within 500 meters) and (iii) the site (indicating levels & contours) to appropriate scales. If not available attach only conceptual plans.

1.2. List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.

1.3. What are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities, details of the existing landuse, disturbance to the local ecology).

1.4. Will there be any significant land disturbance resulting in erosion, subsidence & instability? (Details of soil type, slope analysis, vulnerability to subsidence, seismicity etc may be given).

1.5. Will the proposal involve alteration of natural drainage systems? (Give details on a contour map showing the natural drainage near the proposed project site)

1.6. What are the quantities of earthwork involved in the construction activity-cutting, filling, reclamation etc. (Give details of the quantities of earthwork involved, transport of fill materials from outside the site etc.)

1.7. Give details regarding water supply, waste handling etc during the construction period.

1.8. Will the low lying areas & wetlands get altered? (Provide details of how low lying and wetlands are getting modified from the proposed activity)

1.9. Whether construction debris & waste during construction cause health hazard? (Give quantities of various types of wastes generated during construction including the construction labour and the means of disposal)

2. WATER ENVIRONMENT

2.1. Give the total quantity of water requirement for the proposed project with the breakup of requirements for various uses. How will the water requirement met? State the sources & quantities and furnish a water balance statement.

- 2.2. What is the capacity (dependable flow or yield) of the proposed source of water?
- 2.3. What is the quality of water required, in case, the supply is not from a municipal source? (Provide physical, chemical, biological characteristics with class of water quality)
- 2.4. How much of the water requirement can be met from the recycling of treated wastewater? (Give the details of quantities, sources and usage)
- 2.5. Will there be diversion of water from other users? (Please assess the impacts of the project on other existing uses and quantities of consumption)
- 2.6. What is the incremental pollution load from wastewater generated from the proposed activity? (Give details of the quantities and composition of wastewater generated from the proposed activity)
- 2.7. Give details of the water requirements met from water harvesting? Furnish details of the facilities created.
- 2.8. What would be the impact of the land use changes occurring due to the proposed project on the runoff characteristics (quantitative as well as qualitative) of the area in the post construction phase on a long term basis? Would it aggravate the problems of flooding or water logging in any way?
- 2.9. What are the impacts of the proposal on the ground water? (Will there be tapping of ground water; give the details of ground water table, recharging capacity, and approvals obtained from competent authority, if any)
- 2.10. What precautions/measures are taken to prevent the run-off from construction activities polluting land & aquifers? (Give details of quantities and the measures taken to avoid the adverse impacts)
- 2.11. How is the storm water from within the site managed?(State the provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities provided along with a site layout indication contour levels)
- 2.12. Will the deployment of construction labourers particularly in the peak period lead to unsanitary conditions around the project site (Justify with proper explanation)
- 2.13. What on-site facilities are provided for the collection, treatment & safe disposal of sewage? (Give details of the quantities of wastewater generation, treatment capacities with technology & facilities for recycling and disposal)
- 2.14. Give details of dual plumbing system if treated waste used is used for flushing of toilets or any other use.

3. VEGETATION

- 3.1. Is there any threat of the project to the biodiversity? (Give a description of the local ecosystem with it's unique features, if any)

3.2. Will the construction involve extensive clearing or modification of vegetation? (Provide a detailed account of the trees & vegetation affected by the project)

3.3. What are the measures proposed to be taken to minimize the likely impacts on important site features (Give details of proposal for tree plantation, landscaping, creation of water bodies etc along with a layout plan to an appropriate scale)

4. FAUNA

4.1. Is there likely to be any displacement of fauna- both terrestrial and aquatic or creation of barriers for their movement? Provide the details.

4.2. Any direct or indirect impacts on the avifauna of the area? Provide details.

4.3. Prescribe measures such as corridors, fish ladders etc to mitigate adverse impacts on fauna

5. AIR ENVIRONMENT

5.1. Will the project increase atmospheric concentration of gases & result in heat islands? (Give details of background air quality levels with predicted values based on dispersion models taking into account the increased traffic generation as a result of the proposed constructions)

5.2. What are the impacts on generation of dust, smoke, odorous fumes or other hazardous gases? Give details in relation to all the meteorological parameters.

5.3. Will the proposal create shortage of parking space for vehicles? Furnish details of the present level of transport infrastructure and measures proposed for improvement including the traffic management at the entry & exit to the project site.

5.4. Provide details of the movement patterns with internal roads, bicycle tracks, pedestrian pathways, footpaths etc., with areas under each category.

5.5. Will there be significant increase in traffic noise & vibrations? Give details of the sources and the measures proposed for mitigation of the above.

5.6. What will be the impact of DG sets & other equipment on noise levels & vibration in & ambient air quality around the project site? Provide details.

6. AESTHETICS

6.1. Will the proposed constructions in any way result in the obstruction of a view, scenic amenity or landscapes? Are these considerations taken into account by the proponents?

6.2. Will there be any adverse impacts from new constructions on the existing structures? What are the considerations taken into account?

6.3. Whether there are any local considerations of urban form & urban design influencing the design criteria? They may be explicitly spelt out.

6.4. Are there any anthropological or archaeological sites or artefacts nearby? State if any other significant features in the vicinity of the proposed site have been considered.

7. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

7.1. Will the proposal result in any changes to the demographic structure of local population? Provide the details.

- 7.2. Give details of the existing social infrastructure around the proposed project.
- 7.3. Will the project cause adverse effects on local communities, disturbance to sacred sites or other cultural values? What are the safeguards proposed?

8. BUILDING MATERIALS

- 8.1. May involve the use of building materials with high-embodied energy. Are the construction materials produced with energy efficient processes? (Give details of energy conservation measures in the selection of building materials and their energy efficiency)
- 8.2. Transport and handling of materials during construction may result in pollution, noise & public nuisance. What measures are taken to minimize the impacts?
- 8.3. Are recycled materials used in roads and structures? State the extent of savings achieved?
- 8.4. Give details of the methods of collection, segregation & disposal of the garbage generated during the operation phases of the project.

9. ENERGY CONSERVATION

- 9.1. Give details of the power requirements, source of supply, backup source etc. What is the energy consumption assumed per square foot of built-up area? How have you tried to minimize energy consumption?
- 9.2. What type of, and capacity of, power back-up to you plan to provide?
- 9.3. What are the characteristics of the glass you plan to use? Provide specifications of its characteristics related to both short wave and long wave radiation?
- 9.4. What passive solar architectural features are being used in the building? Illustrate the applications made in the proposed project.
- 9.5. Does the layout of streets & buildings maximise the potential for solar energy devices? Have you considered the use of street lighting, emergency lighting and solar hot water systems for use in the building complex? Substantiate with details.
- 9.6. Is shading effectively used to reduce cooling/heating loads? What principles have been used to maximize the shading of Walls on the East and the West and the Roof? How much energy saving has been effected?
- 9.7. Do the structures use energy-efficient space conditioning, lighting and mechanical systems? Provide technical details. Provide details of the transformers and motor efficiencies, lighting intensity and air-conditioning load assumptions? Are you using CFC and HCFC free chillers? Provide specifications.
- 9.8. What are the likely effects of the building activity in altering the micro-climates? Provide a self assessment on the likely impacts of the proposed construction on creation of heat island & inversion effects?

9.9. What are the thermal characteristics of the building envelope? (a) roof; (b) external walls; and (c) fenestration? Give details of the material used and the U-values or the R values of the individual components.

9.10. What precautions & safety measures are proposed against fire hazards? Furnish details of emergency plans.

9.11. If you are using glass as wall material provides details and specifications including emissivity and thermal characteristics.

9.12. What is the rate of air infiltration into the building? Provide details of how you are mitigating the effects of infiltration.

9.13. To what extent the non-conventional energy technologies are utilised in the overall energy consumption? Provide details of the renewable energy technologies used.

10. Environment Management Plan

The Environment Management Plan would consist of all mitigation measures for each item wise activity to be undertaken during the construction, operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts as a result of the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency such as accidents at the site including fire.

APPENDIX III

(See paragraph 7

GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT DOCUMENT

S.NO	EIA STRUCTURE	CONTENTS
1.	Introduction	<ul style="list-style-type: none">• Purpose of the report• Identification of project & project proponent• Brief description of nature, size, location of the project and its importance to the country, region• Scope of the study – details of regulatory scoping carried out (As per Terms of Reference)
2.	Project Description	<ul style="list-style-type: none">• Condensed description of those aspects of the project (based on project feasibility study), likely to cause environmental effects. Details should be provided to give clear picture of the following:• Type of project• Need for the project• Location (maps showing general location, specific location, project boundary & project site layout)• Size or magnitude of operation (incl. Associated activities required by or for the project)• Proposed schedule for approval and implementation• Technology and process description• Project description. Including drawings showing project layout, components of project etc. Schematic representations of the feasibility drawings which give information important for EIA purpose• Description of mitigation measures incorporated into the project to meet environmental standards, environmental operating conditions, or other EIA requirements (as required by the scope)• Assessment of New & untested technology for the risk of technological failure

3.	Description of the Environment	<ul style="list-style-type: none"> • Study area, period, components & methodology • Establishment of baseline for valued environmental components, as identified in the scope • Base maps of all environmental components
4.	Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures	<ul style="list-style-type: none"> • Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project • Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified • Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components • Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance, Assigning significance) • Mitigation measures
5.	Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul style="list-style-type: none"> • In case, the scoping exercise results in need for alternatives: • Description of each alternative • Summary of adverse impacts of each alternative • Mitigation measures proposed for each alternative and • Selection of alternative
6.	Environmental Monitoring Program	<ul style="list-style-type: none"> • Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, frequency, location, data analysis, reporting schedules, emergency procedures, detailed budget & procurement schedules)
7.	Additional Studies	<ul style="list-style-type: none"> • Public Consultation • Risk assessment • Social Impact Assessment. R&R Action Plans
8.	Project Benefits	<ul style="list-style-type: none"> • Improvements in the physical infrastructure • Improvements in the social infrastructure • Employment potential –skilled; semi-skilled and unskilled • Other tangible benefits

9.	Environmental Cost Benefit Analysis	If recommended at the Scoping stage
10.	EMP	<ul style="list-style-type: none"> • Description of the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored, after approval of the EIA
11	Summary & Conclusion (This will constitute the summary of the EIA Report)	<ul style="list-style-type: none"> • Overall justification for implementation of the project • Explanation of how, adverse effects have been mitigated
12.	Disclosure of Consultants engaged	<ul style="list-style-type: none"> • The names of the Consultants engaged with their brief resume and nature of Consultancy rendered

APPENDIX III A
(See paragraph 7)

CONTENTS OF SUMMARY ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

The Summary EIA shall be a summary of the full EIA Report condensed to ten A-4 size pages at the maximum. It should necessarily cover in brief the following Chapters of the full EIA Report: -

1. Project Description
2. Description of the Environment
3. Anticipated Environmental impacts and mitigation measures
4. Environmental Monitoring Programme
5. Additional Studies
6. Project Benefits
7. Environment Management Plan

APPENDIX IV

(See paragraph 7)

PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District -wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

2.0 The Process:

2.1 The Applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is extending beyond a State or Union Territory, the public hearing is mandated in each State or Union Territory in which the project is sited and the Applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.

2.2 The Applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the Ministry of Environment and Forests and to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

- (a) District Magistrate/s
- (b) Zila Parishad or Municipal Corporation
- (c) District Industries Office
- (d) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests

2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over. The Ministry of Environment and Forests shall promptly display the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report on its website, and also make the full draft EIA available for reference at a notified place during normal office hours in the Ministry at Delhi.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or panchayats etc. They shall also additionally

make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices viz, Ministry of Environment and Forests, District Magistrate etc.

3.0 Notice of Public Hearing:

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7(seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily. A minimum notice period of 30(thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;

3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and only on the recommendation of the concerned District Magistrate the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;

3.4 In the above exceptional circumstances fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member –Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

4.0 The Panel

4.1 The District Magistrate or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

5.0 Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

6.0 Proceedings

6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.

6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Every person present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the Applicant. The summary of the public

hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the Applicant shall also be prepared in the local language and in English and annexed to the proceedings:

6.6 The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate, and the SPCB or UTPCC. The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings which may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the Applicant concerned.

7.0 Time period for completion of public hearing

7.1 The public hearing shall be completed within a period of 45 (forty five) days from date of receipt of the request letter from the Applicant. Therefore the SPCB or UTPCC concerned shall send the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within 8(eight) days of the completion of the public hearing. The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations.

7.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45(forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this notification.

APPENDIX –V
(See paragraph 7)

PROCEDURE PRESCRIBED FOR APPRAISAL

1. The applicant shall apply to the concerned regulatory authority through a simple communication enclosing the following documents where public consultations are mandatory: -

- Final Environment Impact Assessment Report [20(twenty) hard copies and 1 (one) soft copy)]
- A copy of the video tape or CD of the public hearing proceedings
- A copy of final layout plan (20 copies)
- A copy of the project feasibility report (1 copy)

2. The Final EIA Report and the other relevant documents submitted by the applicant shall be scrutinized in office within 30 days from the date of its receipt by the concerned Regulatory Authority strictly with reference to the TOR and the inadequacies noted shall be communicated electronically or otherwise in a single set to the Members of the EAC /SEAC enclosing a copy each of the Final EIA Report including the public hearing proceedings and other public responses received along with a copy of Form -1or Form 1A and scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the proposal .

3. Where a public consultation is not mandatory and therefore a formal EIA study is not required, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and a pre-feasibility report in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule .In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle , the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual plan and stipulate the conditions for environmental clearance . As and when the applicant submits the approved scheme /building plans complying with the stipulated environmental clearance conditions with all other necessary statutory approvals, the EAC /SEAC shall recommend the grant of environmental clearance to the competent authority.

4. Every application shall be placed before the EAC /SEAC and its appraisal completed within 60 days of its receipt with requisite documents / details in the prescribed manner.

5. The applicant shall be informed at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the project proposal.

6. The minutes of the EAC /SEAC meeting shall be finalised within 5 working days of the meeting and displayed on the website of the concerned regulatory authority. In case the project or activity is recommended for grant of EC, then the minutes shall clearly list out the specific environmental safeguards and conditions. In case the recommendations are for rejection, the reasons for the same shall also be explicitly stated.

APPENDIX VI

(See paragraph 5)

COMPOSITION OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACs) FOR CATEGORY B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT`

1. The Expert Appraisal Committees (EAC(s) and the State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) shall consist of only professionals and experts fulfilling the following eligibility criteria:

Professional: The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA/MSc Degree, or (ii) in case of Engineering /Technology/Architecture disciplines, 4 years formal training in a professional training course together with prescribed practical training in the field leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. Law) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/article ship and pass examinations conducted by the concerned professional association (e.g. Chartered Accountancy),or (v) a University degree , followed by 2 years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/IAS/IFS). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.

Expert: A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 15 years of relevant experience in the field, or with an advanced degree (e.g. Ph.D.) in a concerned field and at least 10 years of relevant experience.

Age: Below 70 years. However, in the event of the non-availability of /paucity of experts in a given field, the maximum age of a member of the Expert Appraisal Committee may be allowed up to 75 years

2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields /disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of “Experts” are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:

- **Environment Quality Experts:** Experts in measurement/monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality
- **Sectoral Experts in Project Management:** Experts in Project Management or Management of Process/Operations/Facilities in the relevant sectors.
- **Environmental Impact Assessment Process Experts:** Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process
- **Risk Assessment Experts**
- **Life Science Experts in floral and faunal management**
- **Forestry and Wildlife Experts**

- **Environmental Economics Expert with experience in project appraisal**

3. The Membership of the EAC shall not exceed 15 (fifteen) regular Members. However the Chairperson may co-opt an expert as a Member in a relevant field for a particular meeting of the Committee.

4. The Chairperson shall be an outstanding and experienced environmental policy expert or expert in management or public administration with wide experience in the relevant development sector.

5. The Chairperson shall nominate one of the Members as the Vice Chairperson who shall preside over the EAC in the absence of the Chairman /Chairperson.

6. A representative of the Ministry of Environment and Forests shall assist the Committee as its Secretary.

7. The maximum tenure of a Member, including Chairperson, shall be for 2 (two) terms of 3 (three) years each.

8. The Chairman / Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.

